



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2018/अग्रहायण 22, 1940

No. 495]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2018/AGRAHAYANA 22, 1940

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 13 दिसम्बर, 2018

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9)

संख्या 116-6/2017-एनएसएल-II.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i), (iii) तथा (v) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्वारा दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) कहा जाएगा ।
(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह माह पश्चात् लागू होंगे।
- दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) (इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 2 में,—
(क) खण्ड (क) में “एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस या एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवा) या एकीकृत लाइसेंस जिसके तहत एक्सेस सेवा उपलब्ध कराने का प्राधिकार है” शब्दों के पश्चात् “या एकीकृत लाइसेंस (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर) जिसके पास एक्सेस सेवा उपलब्ध कराने का प्राधिकार है”, को अंतःस्थापित किया जाएगा;
(ख) खंड (खक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(खख) अनुषंगी सेवा प्रभार का अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को भुगतान किए गए प्रभार, जिसमें निम्नलिखित द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभार शामिल हैं:—
(i) भुगतान न किए जाने सहित किसी भी कारण से मोबाइल नम्बर के बंद हो जाने के कारण मोबाइल नम्बर की वापसी को सुगम बनाने हेतु नम्बर रेंज होल्डर द्वारा;
(ii) नंबर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस को डॉउनलोड करने के लिए एक्सेस प्रदाता द्वारा;
(iii) सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग की वापसी के अनुरोध के निष्पादन हेतु दाता प्रचालक द्वारा;
(iv) पोर्ट किए गए सब्सक्राइबर को अपने नेटवर्क पर पुनः जोड़ने के लिए प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा;
(v) ऐसे ‘पोस्ट पेड सब्सक्राइबर’ जिसने अपने नम्बर को पोर्ट करने के पश्चात् दाता प्रचालक की देयताएं न चुकाई हों, उसके मोबाइल नम्बर को बंद करने हेतु दाता प्रचालक द्वारा;

- (ग) खंड (ड.) में शब्द “कोई सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाता अथवा एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाता” के स्थान पर शब्द “एक एक्सेस प्रदाता” को प्रतिस्थापित किया जाएगा,
- (घ) खंड (अख) में शब्द “किसी एमएनपी क्षेत्र में” को शब्द “लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिए” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ड.) खंड (अख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
- (अग) “नेटवर्क सेवा प्रचालक” का अभिप्राय एकीकृत लाइसेंस (वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक) के तहत परिभाषित प्रचालक से है, जो दूरसंचार कोर नेटवर्क का स्वामी है तथा वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक को कोर नेटवर्क सेवा प्रदान करता है ताकि वह एक्सेस नेटवर्क तथा गेटवे के विभिन्न भागों को अन्य नेटवर्कों के साथ जोड़ सके;”
- (च) खंड (ढ) में शब्द “पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण” के स्थान पर शब्द “प्रत्येक सफल पोर्टिंग” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (छ) खंड (न) में, “किसी एक्सेस प्रदाता द्वारा” शब्दों के स्थान पर “क्षेत्र के मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता जिससे नम्बर संबद्ध है” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
3. मूल विनियमों के विनियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
- “5 विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन करने हेतु तंत्र स्थापित करने का दायित्व —** (1) प्रत्येक एक्सेस प्रदाता, अपने मोबाइल नेटवर्क में विशेष पोर्टिंग कोड हेतु अनुरोध करने वाले इसके सब्सक्राइबरों से शॉर्ट मैसेज सेवा (एसएमएस) संदेश प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ एक तंत्र विकसित करेगा तथा इसे उस मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी क्षेत्र में भेजेगा, जिससे मोबाइल नम्बर संबद्ध है;
- (2) प्रत्येक मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क में निम्न के प्रयोजन के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा —
- (क) विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अनुसार दाता प्रचालक द्वारा अग्रेषित विशेष पोर्टिंग कोड हेतु अनुरोध प्राप्त करने के लिए;
- (ख) विशेष पोर्टिंग कोड हेतु अनुरोध को अस्वीकृत किए जाने के लागू आधारों के संबंध में ‘क्वेरी रिस्पांस सिस्टम’ के माध्यम से दाता प्रचालक के डाटाबेस से जांच करना;
- (ग) ऐसे प्रत्येक अनुरोध के लिए एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करना तथा शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के माध्यम से सब्सक्राइबर को इसके संबंध में जानकारी प्रदान करना; और
- (घ) प्राप्तकर्ता प्रचालक से प्राप्त होने वाले ऐसे सब्सक्राइबर के पोर्टिंग अनुरोध के सत्यापन के प्रयोजनार्थ अपने अभिलेखों पर ऐसे विशेष पोर्टिंग कोड को बनाए रखना।
- परन्तु यह कि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता—
- (क) कारपोरेट मोबाइल नम्बरों से प्राप्त अनुरोध की एक विशेष पहचान सुनिश्चित करेगा तथा ‘सी’ उपसर्ग के साथ एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करेगा;
- (ख) एक से अधिक कारपोरेट मोबाइल नम्बरों की पोर्टिंग हेतु एक साथ अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रत्येक कारपोरेट मोबाइल नंबर हेतु एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करेगा।”
4. मूल विनियमों के विनियम 6 में, विनियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- “6क. मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड आवंटन से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया —** (1) विशेष पोर्टिंग कोड हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता अपने डाटाबेस से निम्नलिखित शर्तों की जांच करेगा कि क्या:—
- (क) मोबाइल नम्बर पहले भी पोर्ट हुआ है और यदि ऐसा है तो क्या पिछली पोर्टिंग से लेकर अब तक नब्बे दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई है;
- (ख) इस मोबाइल नम्बर के लिए पोर्टिंग अनुरोध पहले ही प्रक्रियाधीन है; और
- (ग) विशेष पोर्टिंग कोड पहले ही जारी किया जा चुका है तथा इसकी अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है।
- (2) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि उप-विनियम 1 में उल्लिखित खंड (क) अथवा (ख) अथवा (ग) लागू हैं, तो मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता विशेष पोर्टिंग कोड का सृजन नहीं करेगा तथा विशेष पोर्टिंग कोड को सृजित नहीं किए जाने के कारण की एसएमएस द्वारा सब्सक्राइबर को जानकारी देगा।
- (3) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि उप-विनियम 1 में उल्लिखित खंड (क) तथा (ख) और (ग) लागू नहीं हैं, तो वह दाता प्रचालक के डाटाबेस पर रियल टाइम आधार पर तुरंत जांच करेगा कि क्या :—
- (क) यह नम्बर कॉरपोरेट मोबाइल नम्बर है;
- (ख) लंबित बिल के रूप में पोस्ट-पेड सब्सक्राइबर से बकाया भुगतान देय हो, जिन्हें सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार परन्तु विशेष पोर्टिंग कोड के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व जारी किया गया है;
- (ग) पोर्टिंग अनुरोध नये कनेक्शनों की एक्टिवेशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व किया गया है;
- (घ) मोबाइल नम्बर के स्वामित्व में परिवर्तन के अनुरोध पर कार्रवाई चल रही है;

- (ड) पोर्ट किए जाने के लिए आशियत मोबाइल नंबर पर मामला न्यायालय में चल रहा है;
- (च) मोबाइल नंबर की पोर्टिंग न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध की गई है;
- (छ) जहां संविदात्मक दायित्व हों, जिनके संबंध में सब्सक्राइबर करार में एक निर्गम खंड का प्रावधान किया गया हो परंतु सब्सक्राइबर ने ऐसे निर्गम खंड का अनुपालन नहीं किया है;
- (4) दाता प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसका 'क्वेरी रिस्पॉन्स सिस्टम', मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा यथा अपेक्षित, उपविनियम (3) के तहत रीयल टाइम आधार पर प्रतिक्रिया प्रदान करे।
- (5) मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, सब्सक्राइबर के पोर्टिंग अनुरोध को प्राप्तकर्ता प्रचालक से प्राप्ति होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उप-विनियम (3) के तहत प्राप्त की गई जानकारी का रखरखाव करेगा।
- (6) यदि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, यह पाता है कि सब्सक्राइबर का अनुरोध उप-विनियम (3) की खंड (ख) से (छ) में अंतर्विष्ट आधार पर कवर नहीं होता है तो वह सब्सक्राइबर को एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करेगा तथा उसे एसएमएस के माध्यम से सब्सक्राइबर को संप्रेषित करेगा।

परन्तु यह कि कॉरपोरेट मोबाइल नंबर हेतु विशेष पोर्टिंग कोड से पूर्व अक्षर "सी" लगाया जाएगा।

- (7) यदि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, दाता प्रचालक के डाटाबेस से किसी भी तकनीकी कारण से जानकारी की जांच नहीं कर पाता है तो, जैसा कि उप-विनियम (3) में उपबंध किया गया है, वह सब्सक्राइबर को विशेष पोर्टिंग कोड के अनुरोध की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए तथा यह जानकारी देते हुए एक एसएमएस भेजेगा, कि तकनीकी कारण के चलते विशेष पोर्टिंग कोड भेजने में विलम्ब हो रहा है तथा इसे जल्द ही भेज दिया जाएगा।

परन्तु यह कि जहां मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, यह पाता है कि तकनीकी कारण के चलते विशेष पोर्टिंग कोड का सृजन नहीं किया जा सकता है, वह तुरंत ही ऐसे तकनीकी मुद्दे के लिए डॉकेंट बनाकर दाता प्रचालक को सतर्क करते हुए एक संदेश भेजेगा तथा वह ऐसे तकनीकी मुद्दे का समाधान होने पर पुनः दाता प्रचालक के डाटाबेस से जांच करेगा।

- (8) जहां पोर्टिंग किए जाने वाले मोबाइल नम्बर के लिए विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत उपबंधित खंड (ख) से (छ) में अंतर्विष्ट एक या एक से अधिक शर्तें लागू होती हों तो, मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, सब्सक्राइबर को विशेष पोर्टिंग कोड जारी नहीं करेगा तथा मोबाइल सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से विशेष पोर्टिंग कोड सृजित नहीं करने के कारण के संबंध में जानकारी भेजेगा तथा ऐसे रिकॉर्ड को कम से कम छह माह की अवधि के लिए बनाए रखेगा।

5. मूल विनियमों के विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"8 प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:— (1) सब्सक्राइबर से पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति पर प्राप्तकर्ता प्रचालक, सब्सक्राइबर के मोबाइल नम्बर, जिसे पोर्ट किया जाना हो, से दाता प्रचालक के विनिर्दिष्ट लघु कोड, पर एसएमएस के माध्यम से संदेश भेजने को कहता है।

- (2) मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता से विशेष पोर्टिंग कोड की प्राप्ति पर, सब्सक्राइबर इसे पोर्टिंग अनुरोध प्ररूप में अंतर्विष्ट करेगा।
- (3) प्राप्तकर्ता प्रचालक, सब्सक्राइबर से पोर्टिंग अनुरोध प्ररूप के साथ-साथ मोबाइल नम्बर को आवंटित किए गए विशेष पोर्टिंग कोड की प्राप्ति पर यह सुनिश्चित करने के लिए 'सब्सक्राइबर अर्जन प्ररूप' का सत्यापन करेगा कि यह विनियम 7 में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के साथ है।
- (4) प्राप्तकर्ता प्रचालक, 'सब्सक्राइबर अर्जन प्ररूप' में तथ्य को दर्ज करेगा कि उसने सब्सक्राइबर को देख लिया है तथा उसने उसके दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित मूल दस्तावेजों से कर लिया है और उसे सही पाया है।
- (5) प्राप्तकर्ता प्रचालक, चौबीस घंटे की अवधि के भीतर, मोबाइल नंबर, संबंधित विशेष पोर्टिंग कोड तथा वह तारीख जिसको सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग हेतु अनुरोध किया गया है, उसे, एमएनपी क्षेत्र के मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, जिससे पोर्टिंग किए जाने वाले मोबाइल नम्बर का नंबर रेंज होल्डर संबद्ध है, को अग्रेषित करेगा तथा साथ ही जैसे ही पोर्टिंग अनुरोध आरंभ किया जाता है सब्सक्राइबर को पोर्टिंग हेतु उसके अनुरोध को प्रस्तुत किए जाने के बारे में सूचित करते हुए एक एसएमएस भेजेगा।
- (6) कॉरपोरेट मोबाइल नम्बर के मामले में प्राप्तकर्ता प्रचालक, एमएनपी क्षेत्र के मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता जिससे पोर्टिंग किए जाने वाले मोबाइल नम्बर का नंबर रेंज होल्डर संबद्ध है, को ऐसे मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग को अनुमति देते हुए, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र की स्कैन प्रति को भी भेजेगा।

परन्तु यह कि कॉरपोरेट मोबाइल नंबर के लिए, मोबाइल नंबर आदि को मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता को अग्रेषित किए जाने की समयावधि पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति से अड़तालीस घंटे होगी :

परन्तु आगे यह कि कॉरपोरेट मोबाइल नंबर के मामले में एक से अधिक तथा अधिकतम सौ मोबाइल नंबर की पोर्टिंग को अनुमति देते हुए प्राधिकार पत्र की प्रति को अग्रेषित किया जाना, उप-विनियम 6 के प्रयोजनार्थ पर्याप्त होगी:

परन्तु आगे यह भी कि उप-विनियम (6) में विनिर्दिष्ट चौबीस घंटे तथा द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि का आकलन करते समय, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 (1881 का संख्यांक 26) के अधीन घोषित बीच में पड़ने वाले रविवारों तथा सार्वजनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा।

- (7) प्राप्तकर्ता प्रचालक, मोबाइल नंबर की प्रत्येक सफल पोर्टिंग पर मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता को प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार का भुगतान करने का दायी होगा;

परन्तु यह कि प्राप्तकर्ता प्रचालक, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सेवा की गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करेगा।”

6. मूल विनियमों के विनियम 9 में निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“9. मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा की जाने वाली कार्यवाही — (1) विशेष पोर्टिंग कोड हेतु अनुरोध की प्राप्ति पर, संबंधित मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता अपने डाटाबेस से यह जांच करेगा कि:—

(क) मोबाइल नंबर पहले भी पोर्ट हुआ है और पिछली पोर्टिंग से लेकर अब तक नब्बे दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई है;

(ख) इस मोबाइल नंबर के लिए पोर्टिंग अनुरोध पहले ही प्रक्रियाधीन है; और

(ग) विशेष पोर्टिंग कोड पहले ही जारी किया जा चुका है तथा इसकी अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

(2) जहां मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि उप-विनियम 1 में उल्लिखित खंड (क) अथवा (ख) अथवा (ग) लागू हैं, तो वह विशेष पोर्टिंग कोड का सृजन नहीं करेगा तथा विशेष पोर्टिंग कोड को सृजित नहीं किए जाने के कारण की एसएमएस द्वारा सब्सक्राइबर को जानकारी देगा।

(3) जहां मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि उप-विनियम (1) की शर्तें (क) और (ख) और (ग) लागू नहीं हैं, वह विनियम 6क के उप-विनियम (3) में अंतर्विष्ट (क) से (छ) शर्तों हेतु जांच करेगा।

(4) यदि मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि सब्सक्राइबर का अनुरोध विनियम 6क के उप-विनियम (3) की खंड (ख) से (छ) में अंतर्विष्ट आधारों पर कवर नहीं होता है तो वह सब्सक्राइबर को एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करेगा तथा उसे एसएमएस के माध्यम से सब्सक्राइबर को सम्प्रेषित करेगा।

(5) यदि मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता, दाता प्रचालक के डाटाबेस से किसी भी तकनीकी कारण से जानकारी की जांच नहीं कर पाता है तो, जैसा कि विनियम 6 के उप-विनियम (3) में उपबंध किया गया है, वह सब्सक्राइबर को विशेष पोर्टिंग कोड के अनुरोध की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए तथा यह जानकारी देते हुए एक एसएमएस भेजेगा कि तकनीकी कारण के चलते विशेष पोर्टिंग कोड भेजने में विलम्ब हो रहा है तथा इसे जल्द ही भेज दिया जाएगा।

परन्तु यह कि जहां मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता, यह पाता है कि तकनीकी कारण के चलते विशेष पोर्टिंग कोड का सृजन नहीं किया जा सकता है, वह तुरंत ही ऐसे तकनीकी मुद्दे के लिए डॉकेट बनाकर दाता प्रचालक को सतर्क करते हुए एक संदेश भेजेगा तथा वह ऐसे तकनीकी मुद्दे का समाधान होने पर पुनः दाता प्रचालक के डाटाबेस से जांच करेगा।

(6) जहां पोर्टिंग किए जाने वाले मोबाइल नंबर के लिए विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत उपबंधित खंड (ख) से (छ) में अंतर्विष्ट एक या एक से अधिक शर्तें लागू होती हों तो, मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता, सब्सक्राइबर को विशेष पोर्टिंग कोड जारी नहीं करेगा तथा मोबाइल सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से विशेष पोर्टिंग कोड सृजित नहीं करने के कारण के संबंध में जानकारी भेजेगा तथा ऐसे रिकॉर्ड को कम से कम छह माह की अवधि के लिए बनाए रखेगा।

(7) प्राप्तकर्ता प्रचालक से पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त होने पर, मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता इस तथ्य का सत्यापन करेगा कि क्या:—

(क) इस मोबाइल नंबर के लिए पोर्टिंग अनुरोध प्रक्रियाधीन नहीं है;

(ख) पोर्टिंग अनुरोध के साथ प्राप्त विशेष पोर्टिंग कोड, पोर्टिंग किए जाने वाले मोबाइल नंबर के लिए उसके डाटाबेस से सृजित विशेष पोर्टिंग कोड से मेल खाता है;

(ग) विशेष पोर्टिंग कोड पोर्टिंग हेतु अनुरोध प्राप्त होने की तारीख पर वैध है।

(8) जहां उप-विनियम (7) के तहत खंड (क), (ख) और (ग) में अंतर्विष्ट कोई भी शर्त सकारात्मक नहीं हो तो मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता मौजूदा अनुरोध को अस्वीकृत कर देगा तथा ऐसी अस्वीकृति को, प्राप्तकर्ता प्रचालक तथा संबंधित सब्सक्राइबर को अस्वीकृति के कारण सहित संसूचित करेगा।

(9) उप-विनियम (7) की खंड (क), (ख) और (ग) में अंतर्विष्ट शर्तों के सफलतापूर्वक वैधीकरण किए जाने पर, मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता :—

(क) कॉरपोरेट मोबाइल नंबर के अलावा सभी मामलों में, पोर्टिंग हेतु ऐसे अनुरोध को दाता प्रचालक को अंतरा-लाइसेंस सेवा क्षेत्र पोर्टिंग अनुरोधों के मामले में दो कार्यदिवस तथा अंतर-लाइसेंस सेवा क्षेत्र पोर्टिंग अनुरोधों के मामले में चार कार्य दिवसों के पूर्ण हो जाने पर नियत कर भेजेगा तथा सब्सक्राइबर को पोर्टिंग कार्यक्रम के बारे में तथा पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति के समय से चौबीस घंटे तक पोर्टिंग अनुरोध वापस लेने हेतु उपलब्ध विकल्प के बारे में एसएमएस के द्वारा जानकारी प्रदान करेगा;

(ख) कॉरपोरेट मोबाइल नंबरों के मामले में, जहां विशेष पोर्टिंग कोड से पूर्व “सी” वर्ण उपसर्ग लगा है, ऐसे अनुरोधों के ब्योरे तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक से प्राप्त प्राधिकार पत्र की स्कैन की गई प्रति को दाता प्रचालक को पोर्टिंग की अनुमति प्रदान करने के लिए भेजेगा तथा सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति के समय से चौबीस घंटे तक उसे पोर्ट अनुरोध वापस लेने हेतु उपलब्ध विकल्प के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा;

(ग) दाता प्रचालक द्वारा विनियम के उप-विनियम (9) की खंड (ख) के तहत किए गए पोर्टिंग अनुरोध को विनियम 10 में यथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर स्वीकृति प्रदान किए जाने पर, अगले छत्तीस घंटों में पोर्टिंग को नियत कर सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा;

(घ) दाता प्रचालक द्वारा विनियम के उप-विनियम (9) के खंड (ख) के तहत किए गए पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकृत किए जाने पर एसएमएस के माध्यम से सब्सक्राइबर को ऐसे पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकृत किए जाने के कारणों की जानकारी प्रदान करेगा तथा ऐसे रिकार्ड का कम से कम बारह माह के लिए रखरखाव करेगा;

(ड.) विनियम 9 के उप-विनियम (9) के खंड (ख) के तहत किए गए पोर्टिंग अनुरोध के मामले में जहां विनियम 10 में यथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दाता प्रचालक द्वारा कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, पोर्टिंग को अगले छत्तीस घंटों के भीतर नियत कर सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्रदान करेगा।

परन्तु यह कि अंतरा-लाइसेंस सेवा क्षेत्र पोर्टिंग अनुरोध तथा अंतर-लाइसेंस सेवा क्षेत्र पोर्टिंग अनुरोध हेतु क्रमशः दो और चार कार्य दिवसों का आकलन करते समय, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का संख्यांक 26) के अधीन घोषित बीच में पड़ने वाले रविवारों तथा सार्वजनिक अवकाशों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा;

परन्तु आगे यह कि ऐसे मामले जहां विशेष पोर्टिंग कोड को “सी” उपसर्ग के साथ सृजित किया गया हो परन्तु प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध प्राधिकार पत्र को अग्रेषित नहीं किया गया हो, साथ ही ऐसे मामलों में भी जहां विशेष पोर्टिंग कोड से पूर्व “सी” उपसर्ग नहीं लगा हो और प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा प्राधिकार पत्र को अग्रेषित कर दिया गया हो, उन स्थितियों में मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे अनुरोधों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा सब्सक्राइबर तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक को तदनुसार जानकारी दी जाएगी:

परन्तु आगे यह भी कि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करेगा।”

7. मूल विनियमों के विनियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“10. दाता प्रचालक द्वारा कार्यवाही :- (1) दाता प्रचालक अपने नेटवर्क पर क्वेरी रिस्पांस सिस्टम स्थापित करेगा ताकि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, दाता प्रचालक के डाटाबेस तक रीयल टाइम आधार पर पहुंच बना सके तथा विनियम 6क के उपविनियम (3) के तहत खंड (क) से (छ) में सूचीबद्ध शर्तों के संबंध में जांच कर सके।

(2) विनियम 9 के उप-विनियम (9) के खंड (ख) के तहत पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति पर दाता प्रचालक चार कार्य दिवसों के भीतर ऐसे ब्योरे का सत्यापन करेगा तथा जहां यह पाता हो कि पोर्टिंग अनुरोध विनियम 12 के खंड (झ) के तहत कॉरपोरेट मोबाइल नंबर हेतु विनिर्दिष्ट आधार पर कवर होता है, मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता को इसकी जानकारी प्रदान करेगा कि:-

(क) उसे अपने नेटवर्क से मोबाइल नंबर के पोर्टिंग के संबंध में आपत्ति है; अथवा

(ख) उसे मोबाइल नंबर के पोर्टिंग अनुरोध हेतु अनुमति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है;

परन्तु यह कि इस उप-विनियम में यथा निर्दिष्ट कार्यदिवस का आकलन करते समय, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का संख्यांक 26) के अधीन घोषित बीच में पड़ने वाले रविवारों तथा घोषित सार्वजनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा :-

परन्तु आगे यह कि प्रदाता प्रचालक, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करेगा:

8. मूल विनियमों के विनियम 11 में ----

“(क) उप-विनियम (1) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(क) जहां दाता प्रचालक ने विनियम 10 के उप-विनियम (2) की खंड (क) के तहत पोर्टिंग के अनुरोध को अस्वीकृत किए जाने के आधार को इंगित किया हो, तत्काल उसे एसएमएस के माध्यम से मोबाइल सब्सक्राइबर को सूचित करेगा तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक के सूचनार्थ एक प्रति भेजेगा।”

(ख) उप-विनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(7क) मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, नए प्रचालकों के अलावा एक्सेस प्रदाताओं से नम्बर पोर्टिबिलिटी डाटाबेस के डाउनलोड के अनुरोध की प्राप्ति पर अपनी प्रणाली से ऐसे डाउनलोड की अनुमति प्रदान करेगा तथा एक्सेस प्रदाता मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता को डाउनलोड करने हेतु प्रभारों का भुगतान ऐसी दरों पर करेगा जिन्हें समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।”

9. मूल विनियमों के विनियम 12 में -

(क) खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ड.), (च), (छ), (ज) और (झ) का विलोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ज) के पश्चात् पहले परंतुक में “खण्ड (क) से (ज) में विनिर्दिष्ट किन्हीं कारणों के चलते” शब्दों के स्थान पर “खण्ड (झ) में विनिर्दिष्ट आधार” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) खण्ड (ज) के पश्चात् द्वितीय परंतुक में शब्दों “खंड (ज) और (झ)” के स्थान पर शब्दों “खण्ड (झ)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

10. मूल विनियमों के विनियम 13 में निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

“13. पोर्टिंग अनुरोध की वापसी : (1) कोई भी सब्सक्राइबर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा सम्प्रेषित पोर्टिंग के अनुरोध वापस लेने की अवधि के दौरान चौबीस घंटों के भीतर मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को विनिर्दिष्ट लघु कोड के माध्यम से एसएमएस भेजकर पोर्टिंग अनुरोध को वापस कर सकता है।

(2) जहां, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग अनुरोध वापस लेने का निवेदन मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को प्राप्तकर्ता आपरेटर द्वारा, पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत करने के चौबीस घंटों के भीतर प्राप्त हो गया है, इस स्थिति में वह पोर्टिंग को रद्द करेगा तथा भावी पोर्टिंग हेतु इस विशेष पोर्टिंग कोड को अमान्य करेगा, तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक तथा सब्सक्राइबर को सूचित करेगा: बशर्ते कि दाता प्रचालक, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को इस प्रकार के रद्दीकरण हेतु प्रभारों का भुगतान करेगा।

(3) यदि मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा मोबाइल नम्बर पोर्टिंग का अनुरोध प्रस्तुत करने के चौबीस घंटे बाद पोर्टिंग अनुरोध वापस लेने का अनुरोध प्राप्त होता है तो वह सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा कि पोर्टिंग के अनुरोध को वापस लेने का समय समाप्त हो गया है तथा वह विनियम 9 के उप विनियम (9) की खंड (क) (ग) और (ड़) के अनुसार एक्टिवेट करने तथा डि-एक्टिवेट करने की नियत तारीख एवं समय के अनुरूप कार्यवाही करेगा।”

11. मूल विनियमों के विनियम 14 में उप-विनियम (5) में शब्दों “प्राप्तकर्ता प्रचालक को” के बाद तथा “ऐसे बकाया बिलों के विवरण” शब्दों से पूर्व, “बिल की तारीख, भुगतान की अंतिम तारीख, नोटिस की तारीख तथा सब्सक्राइबर को दी गई नोटिस की अवधि सहित” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

12. मूल विनियमों के विनियम 15 में:—

(क) उप-विनियम (1) में “समय-समय पर यथानिर्दिष्ट” के पश्चात तथा “प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार” शब्दों के पहले, “और सब्सक्राइबर पुनर्संयोजन प्रभार” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (4) में द्वितीय परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु आगे यह कि यदि सब्सक्राइबर प्रथम परंतुक में संदर्भित भुगतान करता है, तथा ऐसे भुगतान का साक्ष्य, सेवा बंद करने के साठ दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता प्रचालक को उपलब्ध कराता है तो सब्सक्राइबर की सेवाओं को तुरंत बहाल किया जाएगा तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को इस प्रकार सेवा बहाली के बारे में सूचित करेगा तथा ऐसे मोबाइल नम्बर के संबंध में इसके नंबर रेंज होल्डर को वापस करने के अनुरोध को वापस लेगा।”

13. मूल विनियमों के विनियम 16 में, —

(क) उप-विनियम (2) में “पोर्टिंग” के बाद तथा “और डिपिंग” शब्दों से पूर्व, “विशेष पोर्टिंग कोड आवंटन तथा सत्यापन” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(3) (क) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, मोबाइल सब्सक्राइबर से विशेष पोर्टिंग कोड हेतु प्राप्त अनुरोधों की संख्या, सफलतापूर्वक आवंटित विशेष पोर्टिंग कोड की संख्या तथा ऐसे अनुरोधों की संख्या जहां कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई अथवा दाता प्रचालक द्वारा विलम्ब से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, के संबंध में रिपोर्ट सृजित करेगा तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर कोई अपेक्षित अन्य रिपोर्ट भी तैयार करेगा।”

(ग) उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(5क) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, प्राप्तकर्ता प्रचालक के नेटवर्क में पोर्ट किए गए सब्सक्राइबर के पुनर्संयोजन को सुगम बनाने हेतु प्रभारों के संबंध में प्रासंगिक विवरणों के साथ, मासिक आधार पर बिल प्रदान करेगा तथा ऐसे बिलों को आगामी माह की दस तारीख से पूर्व अथवा ऐसे आवधिक अंतरालों पर तथा ऐसी समय-सीमाओं के भीतर, जो कि पारस्परिक सहमति से निश्चित की जाए, संबंधित प्राप्तकर्ता प्रचालक को वितरित करेगा।

(5ख) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, नंबर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस को डाउनलोड करने के लिए प्रभारों के संगत ब्योरे के साथ बिल तैयार करेगा तथा मासिक आधार पर ऐसे बिलों को संबंधित एक्सेस प्रदाता को आगामी माह की दस तारीख अथवा ऐसे आवधिक अंतरालों पर तथा ऐसी समय-सीमाओं के भीतर, जो कि पारस्परिक सहमति से निश्चित की जाए, वितरित करेगा।

(5ग) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता सब्सक्राइबर के पोर्टिंग अनुरोध वापस लेने के निवेदन के निष्पादन हेतु प्रभारों के संगत ब्योरे सहित बिलों को संबंधित दाता प्रचालक को मासिक आधार पर प्रदान करेगा तथा ऐसे बिलों को संबंधित दाता प्रचालक को आगामी माह की दस तारीख अथवा ऐसे आवधिक अंतरालों पर तथा ऐसी समय-सीमाओं के भीतर, जो कि पारस्परिक सहमति से निश्चित की जाए, वितरित करेगा।

(5घ) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, गैर भुगतान सहित किसी भी कारण के चलते कनेक्शन काटे जाने के पश्चात् मोबाइल नम्बर की वापसी हेतु प्रभारों के संगत ब्योरे सहित नंबर रेंज होल्डर को मासिक आधार पर प्रदान करेगा तथा ऐसे बिलों को संबंधित नंबर रेंज होल्डर को आगामी माह की दस तारीख अथवा ऐसे आवधिक अंतरालों पर तथा ऐसी समय-सीमाओं के भीतर, जो कि पारस्परिक सहमति से निश्चित की जाए, वितरित करेगा।

(घ) उप-विनियम (6) में शब्द “प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभारों” के पश्चात् तथा “के लिए बिल” शब्दों से पूर्व, शब्द “और सब्सक्राइबर पुनर्संयोजन प्रभारों” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

14. मूल विनियम के विनियम 17क को निम्नलिखित विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“17क – विनियम 6क, अथवा विनियम 8 अथवा विनियम 9 अथवा विनियम 10 अथवा विनियम 11 अथवा विनियम 12 के उपबंधों के उल्लंघन के परिणाम ——— (1) यदि कोई एक्सेस प्रदाता अथवा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, विनियम 8 के उप-विनियम (5) अथवा विनियम 9 के उप-विनियम (9) अथवा विनियम 10 के उप-विनियम (2) अथवा विनियम 11 के उप-विनियम (4) अथवा विनियम 11 के उप-विनियम (6) का उल्लंघन करता है तो, उसके लाइसेंस की निबंधन और शर्तों, अधिनियम अथवा नियमों तथा विनियमों के उपबंधों, अथवा जारी आदेशों अथवा इसके तहत जारी निर्देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वित्तीय अनुत्साहन के माध्यम से ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो कि प्रत्येक उल्लंघन के मामले में पांच हजार रुपये अथवा जैसा प्राधिकरण आदेश निदेश देगा, से अनधिक नहीं होगी।

(2) यदि कोई एक्सेस प्रदाता अथवा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, विनियम 6क अथवा विनियम 10 के उप-विनियम (1) अथवा विनियम 12 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो, उसके लाइसेंस की निबंधन और शर्तों, अधिनियम अथवा नियमों तथा विनियमों के उपबंधों, अथवा जारी आदेशों अथवा इसके तहत जारी निर्देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वित्तीय अनुत्साहन के माध्यम से ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो कि प्रत्येक उल्लंघन के मामले में पांच हजार रुपये अथवा जैसा प्राधिकरण आदेश निदेश देगा, से अनधिक नहीं होगी।

(3) उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) के तहत वित्तीय अनुत्साहन के माध्यम से किसी धनराशि के भुगतान के संबंध में कोई आदेश प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया जाएगा, जब तक कि सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा पाए गए विनियम के उल्लंघन के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

एस. के. गुप्ता, सचिव

टिप्पणी 1: मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में दिनांक 23 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 116-4/2009-एमएन (खंड II) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था तथा निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किया गया था:

- (i) दिनांक 28 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 116-1/2010 (2010 का 1)
- (ii) दिनांक 02 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या 116-1/2010 (2010 का 5)
- (iii) दिनांक 08 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 116-5/2012 (2012 का 16)
- (iv) दिनांक 19 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 116-5/2012 (2012 का 19)
- (v) दिनांक 22 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 116-4/2013 (2013 का 9)
- (vi) दिनांक 25 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 116-19/2014 (2015 का 3)

टिप्पणी 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन इन विनियमों के उद्देश्यों तथा कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में अंतरा लाइसेंस सेवा क्षेत्र मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन करने के लिए बुनियादी कारोबार प्रक्रिया की रूपरेखा तय करते हुए 23 सितंबर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किया था। एमएनपी की सुविधा पायलट आधार पर 25 नवंबर, 2010 को हरियाणा सेवा क्षेत्र में शुरू की गई थी और 20 जनवरी 2011 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था। प्रारंभ में एमएनपी की सुविधा केवल लाइसेंस क्षेत्र के भीतर उपलब्ध कराई गई थी। बहरहाल, “एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी” के संबंध में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के अनुसार, 3 जुलाई, 2015 से पूर्ण एमएनपी को क्रियान्वित किया गया था।
- दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग के अनुरोध अस्वीकार करने के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनपीएसपी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समय-समय पर निगरानी की जाती है। अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि की रिपोर्ट का विश्लेषण करने से पता चलता है कि सभी श्रेणियों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पोर्टिंग अनुरोधों को अस्वीकार करने का औसत 11.16 प्रतिशत (प्रतिमाह कुल अस्वीकरण औसत 5.87 लाख) था और “विशेष पोर्टिंग कोड मिसमैच” और “विशेष पोर्टिंग कोड समाप्त” के आधार पर अस्वीकरण, कुल अस्वीकरण का लगभग 40 प्रतिशत है। प्रतिमाह 52.35 लाख के औसत पोर्टिंग अनुरोधों के साथ, “विशेष पोर्टिंग कोड मिसमैच” और “विशेष पोर्टिंग कोड समाप्त” के आधार पर औसत अस्वीकरण मिलकर उपरोक्त अवधि के लिए लगभग 2.3 लाख थे। तदनुसार, दूरसंचार मोबाइल सब्सक्राइबरों को पेश आ रही दिक्कतों का समाधान करने के लिए 16 अगस्त, 2017 का मसौदा को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन), विनियम, 2017 जारी किया गया था, जिसके तहत हितधारकों से 28 सितंबर 2017 तक टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इस ड्राफ्ट विनियम में यह परिकल्पना की गई थी कि दाता प्रचालक विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने पर विशेष पोर्टिंग कोड के कंटेन्ट और वैधता को एमएनपीएसपी को अग्रेषित करेंगे, जिनसे बाद में, सब्सक्राइबर द्वारा प्रस्तुत विशेष पोर्टिंग कोड की सत्यता और वैधता की पुष्टि करने के लिए प्राप्तकर्ता ऑपरेटर संपर्क कर सकेंगे।
- हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच और विश्लेषण किया गया था। इन टिप्पणियों के अध्ययन में पाया गया था कि ड्राफ्ट एमएनपी विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों, जैसा कि उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किया गया है, के अलावा, हितधारकों ने कई नए मुद्दे उठाए थे और एक नई व्यवस्था का सुझाव दिया था। ड्राफ्ट सातवें संशोधन पर परामर्श के दौरान, हितधारकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों/टिप्पणियों पर सभी हितधारकों से परामर्श करने की जरूरत महसूस की गई।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, प्राधिकरण ने मौजूदा एमएनपी प्रक्रिया की समीक्षा की और इसमें सुधार करने के साथ इसे दूरसंचार सब्सक्राइबर्स के लिए कुशल और सुगम बनाने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी। तदनुसार, पहचाने गए मुद्दों और एमएनपी प्रक्रिया में प्रस्तावित संशोधन करने के लिए 3 मई, 2018 तक टिप्पणियां और 17 मई, 2018 तक प्रति-टिप्पणियां मांगने के लिए 6 अप्रैल, 2018 को हितधारकों से टिप्पणियां लेने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया। इस परामर्श पत्र के उत्तर में तेरह (13) टिप्पणियां और पांच (5) प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुई थी। 11 जून, 2018 को भादूविप्रा के मुख्यालय में एक खुला मंच चर्चा का भी आयोजन किया गया था।
5. खुला मंच चर्चा के दौरान प्रस्तुत हितधारकों की टिप्पणियां, प्रति-टिप्पणियां और विचारों की जांच करने और समुचित विमर्श के बाद, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के लिए ड्राफ्ट सातवां संशोधन तैयार किया गया और हितधारकों की टिप्पणी के लिए 25 सितंबर, 2018 को इसे भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। प्रारंभ में, ड्राफ्ट संशोधन इस आधार पर तैयार किया गया था कि विनियमों के संशोधन के कार्यान्वयन से पहले केन्द्रीय निगरानी प्रणाली (सीएमएस) के लिए सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां (एलईए) जुड़ जाएंगी और तदनुसार, पोर्टिंग के लिए एक दिन के समय का प्रस्ताव किया गया था। बहरहाल, इस बीच दूरसंचार विभाग ने प्राधिकरण को सूचित किया कि सीएमएस के लिए एलईए के साथ लेने में ज्यादा समय लग सकता है। दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र द्वारा सुझाव दिया कि अंतरा-लाइसेंस सेवा क्षेत्र (अंतरा-एलएसए) और अंतर-लाइसेंस सेवा क्षेत्र (अंतर-एलएसए) के लिए क्रमशः दो दिन और चार दिन की समय-सीमा पर विचार किया जाए। इसे लागू करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 16 अगस्त, 2018 को भादूविप्रा में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और एमएनपीएसपी के साथ एक बैठक की गई थी।
6. ड्राफ्ट सातवें संशोधन पर नौ हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थी, जिनका गहराई से विश्लेषण किया गया था। विस्तृत विश्लेषण और समुचित विमर्श के आधार पर दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के लिए सातवां संशोधन विनियम, 2018 जारी किया जा रहा है।
7. प्रमुख मुद्दों पर स्पष्टीकरण और मूल विनियमों में किए गए संशोधनों का विवरण नीचे दिया गया है:-

विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण के लिए क्रियाविधि स्थापित करने का दायित्व

8. ड्राफ्ट संशोधन में यह परिकल्पना की गई थी कि एमएनपीएसपी को विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने और अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कराने के इच्छुक सब्सक्राइबर को सूचित करने का काम सौंपा जाए। तदनुसार, संशोधन विनियम के विनियम 6क में, विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करने से पहले मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए एक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संशोधन प्रक्रिया में, विशेष पोर्टिंग कोड के अनुरोध एक्सेस प्रदाता द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और ये उसी समय संबंधित एमएनपीएसपी को अग्रेषित किए जाएंगे। एमएनपीएसपी यथा निर्धारित, दाता प्रचालक के डाटाबेस के साथ रीयल टाइम आधार पर अपेक्षित जांचें करने के बाद, विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करेगा और इसे सब्सक्राइबर को भेजेगा।
9. इसके उत्तर में, कुछ हितधारकों ने ड्राफ्ट संशोधन में किए गए प्रावधानों के लिए अपने समर्थन को दोहराया है। इन हितधारकों का मानना है कि विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण में प्रस्तावित बदलावों से तेजी से पोर्टेबिलिटी मुद्दा कराने में मदद मिलेगी और यह पोर्टिंग अस्वीकरण की समस्या का भी समाधान कर देगा। हितधारकों का यह भी मत था कि तटस्थ और तृतीय पक्ष होने के नाते एमएनपीएसपी विशेष पोर्टिंग कोड की निष्पक्ष और समय पर वितरण सुनिश्चित कर सकता है। एक हितधारक ने मौजूदा प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं करने की मांग के साथ कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाता विशेष पोर्टिंग कोड को सृजन करने से संबंधित एमएनपी विनियमों के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं। विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने का काम ऑपरेटर के पास ही रहना चाहिए और सृजन नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति से मामला-दर-मामला के आधार पर निपटना चाहिए। हितधारक ने यह भी कहा कि एमएनपीएसपी के सिस्टम में तकनीकी खराबियां आने की भी संभावना हो सकती है।
10. ड्राफ्ट संशोधन में, यह दर्शाया गया था कि "विशेष पोर्टिंग कोड मिसमैच" और "समाप्त विशेष पोर्टिंग कोड" के आधार पर पोर्टिंग अनुरोधों के अस्वीकरण की संख्या, अप्रैल, 2017 से मई, 2018 की अवधि के लिए पोर्टिंग अनुरोधों के कुल अस्वीकरण का लगभग 45 प्रतिशत थी। इसके अलावा, 'भुगतान देय' और '90 दिन से कम' की श्रेणियों के तहत औसत अस्वीकरण क्रमशः 34.50 प्रतिशत और 12.89 प्रतिशत थे।
11. ड्राफ्ट संशोधन में, प्राधिकरण ने पहले ही उपरोक्त तथ्यों को महत्व दिया है और यह पाया कि जून से सितंबर, 2018 के दौरान भी अस्वीकरण की मुख्य श्रेणियों में इन में कोई सुधार नहीं हुआ है। मौजूदा प्रक्रिया में सब्सक्राइबर को अपना पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत करने के चार से सात दिनों बाद यह सूचना मिलती है कि उसका पोर्टिंग अनुरोध अस्वीकृत हो गया है।
12. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों और प्रेक्षकों की जांच की है। प्राधिकरण विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने से पहले दाता प्रचालक से पूछताछ के जरिये पोर्टिंग की शर्तों की प्रारंभिक जांच करने के लिए एमएनपीएसपी को अधिकृत करने के लिए सहमत है। तदनुसार, दाता प्रचालक के नेटवर्क पर सब्सक्राइबर द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने के अनुरोध के संबंध में शॉर्ट कोड 1900 संबंधित एमएनपीएसपी को अग्रेषित किया जाएगा जो संशोधन विनियमों के विनियम 6क में निर्धारित शर्तों की जांच करके मोबाइल सब्सक्राइबर को विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित और वितरित करेगा।

एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन और वितरण करने की संशोधित क्रियाविधि कार्यान्वित करना

13. एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन और वितरण करने की संशोधित क्रियाविधि के कार्यान्वयन के मुद्दे पर कुछ हितधारकों ने यह चिंता जाहिर की है कि इसके लिए बदलावों को समाहित करने के लिए एमएनपीएसपी की ओर से मौजूदा सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त, मौजूदा अवसंरचना के साथ एमएनपीएसपी के लिए रीयल टाइम के आधार पर अधिक संख्या में ट्रान्जेक्शन को संभालना मुश्किल होगा और परिणामस्वरूप, लागतों में वृद्धि होगी। कुछ हितधारकों ने कहा कि प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता प्रचालक और दाता प्रचालक के डाटाबेस में उपलब्ध सब्सक्राइबर की सूचना को एमएनपीएसपी के साथ साझा करना शामिल है, जिससे न केवल दूरसंचार सेवा प्रदाता के डाटाबेस की सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा बल्कि यह गोपनीयता की उन शर्तों का भी उल्लंघन होगा, जिनके तहत सब्सक्राइबर्स से सूचना एकत्रित की जाती है। इसके फलस्वरूप एमएनपीएसपी द्वारा अपने व्यवसायिक लाभ के लिए सूचना का दुरुपयोग भी किया जा सकता है।
14. एक और हितधारक ने कहा कि एमएनपीएसपी के लिए मौजूदा लाइसेंस शर्तों में एमएनपीएसपी की भूमिका को शामिल नहीं किया गया है जैसा कि प्रस्तावित प्रक्रिया में किया गया है। कुछ हितधारकों ने कहा है कि एमएनपीएसपी की जवाबदेही बढ़ाने के लिए, एमएनपीएसपी की भूमिका और जिम्मेदारियों को एमएनपी विनियमों और लाइसेंस की शर्तों में स्पष्टता से परिभाषित किया जाना चाहिए।
15. एक हितधारक का यह मत था कि एमएनपीएसपी लाइसेंस नवीकरण के लिए मार्च 2019 में आएं इसलिए दूरसंचार विभाग, भादूविप्रा और एमएनपीएसपी को इन शर्तों पर बात करनी चाहिए और एमएनपीएसपी की विस्तारित जिम्मेदारियों की सूची पर सहमत होना चाहिए तथा विस्तारित भूमिका को पूरा करने के लिए निष्पक्ष और पर्याप्त क्षतिपूर्ति पर भी सहमत होना चाहिए।
16. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों की जांच के पश्चात् यह मत बनाया है कि संशोधित प्रक्रिया को कार्यान्वित करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए; और इसे दूरसंचार सेवा प्रदाता एवं एमएनपीएसपी की ओर से हार्डवेयर और/या सॉफ्टवेयर में इष्टतम बदलाव के साथ कार्यान्वित किया जा सकता है। यहां पर यह उल्लेख करना समीचीन है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता और एमएनपीएसपी के सिस्टम में पूरे एमएनपी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मौजूदा गेटवे लिंक के जरिये पहले से कनेक्टिविटी है। सब्सक्राइबर्स, ऑपरेटर्स और एमएनपीएसपी पर विशेष पोर्टिंग कोड वितरण की संशोधित प्रक्रिया के प्रभाव का न्यूनीकरण करने के लिए एमएनपीएसपी और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच के मौजूदा गेटवे का उपयोग दाता प्रचालक द्वारा सब्सक्राइबर्स से प्राप्त विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोधों को एसएमएस, जैसा कि मौजूदा प्रक्रिया में है, के जरिये भेजने के लिए किया जा सकता है। दाता

प्रचालक द्वारा अपने सब्सक्राइबर्स से प्राप्त विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोधों को अगली कार्यवाही के लिए तुरंत संबंधित एमएनपीएसपी को अग्रणी किया जाएगा। मौजूदा अवसंरचना/गेटवे का इस्तेमाल संशोधित प्रक्रिया को कार्यान्वित करने में लाभप्रद तरीके से किया जा सकता है।

17. लाइसेंस के नियम एवं शर्तों के कारण उत्पन्न चुनौतियों के संबंध में प्राधिकरण एमएनपीएसपी की लाइसेंस की शर्तों में उचित संशोधन करके, यदि उचित समझा गया तो, संशोधित परिदृश्य में एमएनपीएसपी की भूमिका को शामिल करने के लिए इस मामले पर दूरसंचार विभाग से अलग से कार्यवाही करेगा।

शर्तों की वैधता और विशेष पोर्टिंग कोड को सृजन/वितरण करने के लिए संशोधित प्रक्रिया

18. ड्राफ्ट संशोधन के जरिये विनियम 6क के उपविनियम (3) के तहत खंड (क) से (ज) में दी गई शर्तों के बारे में जांच के लिए दाता प्रचालक के डाटाबेस तक रीयल टाइम आधार पर पहुंचने में मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता (एमएनपीएसपी) को समर्थ बनाने के लिए एक क्वेरी रिसांस सिस्टम स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
19. विनियम 6क के उपविनियम (3) के तहत सूचीबद्ध पूछताछ के संबंध में, एक हितधारक ने सुझाव दिया है कि वह ऐसी पूछताछ के उत्तर “हां” या “नहीं” के रूप में प्रदान करेगा, और प्रक्रिया में किसी भी डाटा का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा। हितधारक ने यह भी कहा है कि यदि सब्सक्राइबर “प्रीपेड” या “पोस्टपेड” है तो जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पोर्टिंग प्रक्रिया में इसका कोई औचित्य नहीं है।
20. हितधारक ने पोर्टिंग प्रक्रिया के सुगम परिचालन, फर्जी पोर्टिंग की रोकथाम करने, सब्सक्राइबर्स की शिकायतों का समाधान करने के लिए एमएनपीएसपी की जवाबदेही बढ़ाने की बात कही है। हितधारक ने कुछ कार्यों के सुझाव दिए हैं जैसे कि सभी ऑपरेटरों को रीयल टाइम रिपोर्ट और सूचना उपलब्ध कराना, पोर्टिंग अनुरोध के चरणों को पूरा करने के बारे में सब्सक्राइबर्स को सूचना देना, अनुरोध की स्थिति बताना (यह स्वीकृत या अस्वीकृत हो गई है), सब्सक्राइबर्स की एमएनपी संबंधी शिकायतों का समाधान करना और प्राप्तकर्ता प्रचालक/दाता प्रचालक एवं एमएनपीएसपी के बीच सहमति योग्य सर्विस लेवल एग्रीमेंट आदि। हितधारक ने एमएनपीएसपी की ओर से किसी चूक के मामले में उचित जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया है।
21. एक हितधारक ने अंतिम विनियमों के साथ एपीआई विशिष्टियां जारी करने का अनुरोध किया है ताकि वो काम शुरू करने में समर्थ हो सके। एक अन्य हितधारक ने कहा कि यह अनुमान है कि दाता प्रचालक के डाटाबेस में सब्सक्राइबर की सूचना के बारे में पूछताछ उसी यूआरएल में एसओएपी संदेशों का इस्तेमाल करके की जाएगी जो आज सभी एक्सेस प्रदाताओं के लिए उपलब्ध है। इससे एमएनपीएसपी और एक्सेस प्रदाता की ओर से कम से कॉन्फिगरेशन/हार्डवेयर बदलाव के साथ दाता प्रचालक से वांछित सूचना लेने में मदद मिलेगी।
22. एक हितधारक ने क्वेरी रिसांस सिस्टम का विरोध करते हुए कहा है कि इससे न केवल दूरसंचार सेवा प्रदाता के डाटाबेस की सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा बल्कि यह गोपनीयता की उन शर्तों का भी उल्लंघन होगा, जिनके तहत सब्सक्राइबर्स से सूचना एकत्रित की जाती है। हितधारक ने यह भी कहा कि सब्सक्राइबर की पूर्ण सूचना को एमएनपीएसपी को एक्सेस देने से एमएनपीएसपी द्वारा अपने व्यवसायिक लाभ के लिए सूचना का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए सुझाव दिया कि एमएनपी अनुरोध को स्वीकार/अस्वीकार करने के कारणों की जांच ऑपरेटरों द्वारा ही की जानी चाहिए और विनियमों के गैर-अनुपालन के संबंध में कोई असामान्यता से मामला-दर-मामला के आधार पर निपटना चाहिए।
23. सब्सक्राइबर की सूचना की गोपनीयता और एमएनपीएसपी द्वारा अपने व्यवसायिक लाभ के लिए इसके संभावित दुरुपयोग के संबंध में हितधारक की टिप्पणी की जांच की गई है। इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि एमएनपीएसपी को टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंसर द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। गोपनीयता खंडों के अनुपालन हेतु इन संस्थाओं को जारी किए गए लाइसेंस के तहत पर्याप्त प्रावधान हैं।
24. “हां” या “नहीं” के रूप में पूछताछ के उत्तरों को साझा करने के एक हितधारक के सुझाव पर सहमति हो सकती है और कोई अन्य सूचना जैसे कि वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना एमएनपीएसपी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
25. कनेक्शन अर्थात् प्रीपेड या पोस्टपेड की स्थिति जानने का मकसद प्रीपेड कनेक्शन के मामले में देय बकायों के लिए पूछताछ को हटाना था। प्राधिकरण ने हितधारकों के सुझावों पर गौर किया और उनका यह मानना है कि प्रीपेड या पोस्टपेड की स्थिति से संबंधित पूछताछ को हटाया जा सकता है और सभी मामलों अर्थात् प्रीपेड और पोस्टपेड में “देय बकायों” के लिए एमएनपीएसपी द्वारा दूसरी पूछताछ बनाई जा सकती है। सभी प्रीपेड कनेक्शनों और उन पोस्टपेड कनेक्शनों, जिनमें विशेष पोर्टिंग कोड के अनुरोध की तारीख से पहले कोई देय बकाया नहीं है, के मामले में उत्तर “नहीं” होगा। उन पोस्टपेड कनेक्शनों के लिए उत्तर “हां” होगा, जिनमें लंबित बिल या बिलों, जैसा भी मामला हो, के रूप में सब्सक्राइबर से भुगतान बकाया है, जो सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार मगर विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोध की तारीख से पहले जारी किए गए हैं। उपरोक्त के अनुसार, एमएनपीएसपी को शर्त (क) से (छ) के लिए पूछताछ करनी होगी जैसा कि विनियम 6क के उपविनियम (3) में परिभाषित किया गया है।

संशोधित परिदृश्य में एमएनपीएसपी और दूरसंचार सेवा प्रदाता की भूमिका की निगरानी करने के लिए प्रणाली

26. संशोधित प्रक्रिया में एमएनपीएसपी की जिम्मेदारी और भूमिका के मुद्दे पर कुछ हितधारकों ने कहा है कि उस प्रत्येक कार्य के लिए विस्तृत सेवा स्तर समझौते के लिए प्रावधान होना चाहिए जो एमएनपीएसपी द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा। कुछ हितधारकों ने निगरानी के लिए नियमित रिपोर्टिंग प्रणाली की मांग की है जबकि दूसरे हितधारक ने सुझाव दिया है कि भादूविप्रा द्वारा आवधिक निरीक्षण, निगरानी और जांच की जाए।
27. बदले हुए परिदृश्य में एमएनपीएसपी और दूरसंचार सेवा प्रदाता की जवाबदेही एक महत्वपूर्ण पहलु है। सौंपे गए कार्य के लिए मापयोग्य मानदण्डों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। तदनुसार, प्राधिकरण का यह मत है कि मौजूदा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अलावा, मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता मोबाइल सब्सक्राइबर्स से विशेष पोर्टिंग कोड से प्राप्त विशेष पोर्टिंग कोड के अनुरोधों की संख्या, सफलतापूर्वक आवंटित विशेष पोर्टिंग कोड की संख्या के संबंध में आंकड़े/रिपोर्ट के विशिष्ट सेट या समय-समय पर यथा अपेक्षित अन्य रिपोर्ट सृजन करेगा।
28. विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण में एमएनपीएसपी के प्रभाव और भूमिका की निगरानी करने के संबंध में कुछ हितधारकों का मत है कि संशोधित प्रक्रिया में एमएनपीएसपी द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर लागू सेवा गुणवत्ता के उचित मानदण्ड निर्धारित किए जाएं। विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण और पोर्टिंग प्रक्रिया के सुगम परिचालन के लिए एमएनपीएसपी और दूरसंचार सेवा प्रदाता की जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियत मानदण्ड जैसे, प्राप्त विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोधों की संख्या, सृजन किए गए विशेष पोर्टिंग कोडों की संख्या और तकनीकी विफलता के मामले या एमएनपीएसपी द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर देने में असमर्थता को ध्यान में रखकर मानदण्ड निर्धारित किए जा सकते हैं।
29. प्राधिकरण को सेवा गुणवत्ता के मानदण्डों के रूप में विशेष पोर्टिंग कोड आवंटन और वितरण की प्रक्रिया को शामिल करने के संबंध में हितधारकों के सुझाव उचित लगे हैं। प्राधिकरण इस बात से भी अवगत है कि एमएनपीएसपी द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर के प्रसार में दाता प्रचालक की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, संशोधित परिदृश्य में एमएनपीएसपी और प्राप्तकर्ता प्रचालक की भूमिका को बढ़ाया गया है और इसलिए इन्हें मापयोग्य सेवा गुणवत्ता मानदण्डों का भाग भी बनाया जा सकता है। ये सेवा गुणवत्ता के मानदण्ड, प्राधिकरण द्वारा अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता

30. ड्राफ्ट संशोधन में, विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता, जम्मू एवं कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर को छोड़कर, जहां अगले निर्णय तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अन्य सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए चार दिन करने का प्रस्ताव किया गया था।
31. कुछ हितधारकों ने कहा है कि विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता को 15 से घटाकर 4 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है। इन हितधारकों ने सुझाव दिया है कि विशेष पोर्टिंग कोड समाप्ति अवधि को 4 दिन से बढ़ाकर 7 दिन किया जाए क्योंकि वर्तमान सब्सक्राइबर सत्यापन और प्राप्त करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।
32. विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता को मौजूदा 15 दिनों से घटाकर 4 दिन करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि एमएनपीएसपी के लिए सुगम्य डाटाबेस के कुछ नियत कारणों जैसे भुगतान बकाये, कानूनी पहलु आदि परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और कुछ इनमें कुछ दिनों के भीतर बदलाव हो सकता है। सब्सक्राइबर सत्यापन और प्राप्त करने की प्रक्रिया के पहलुओं पर दूरसंचार सेवा प्रदाता नए कनेक्शनों के लिए वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया का परीक्षण कर रहे हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा परीक्षण और पायलट पूरा किए जाने के बाद, यह आशा है कि वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया शुरू की जाएगी और यह अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त रूप से कुशल होगी। इसलिए विशेष पोर्टिंग कोड की कम अवधि उचित है। इसके अतिरिक्त, समाप्त होने के पश्चात सब्सक्राइबर द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड फिर से सृजन की जा सकती है; तदनुसार, प्राधिकरण का यह मत है कि विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता वर्तमान 15 दिनों के स्थान पर 4 दिन की होगी।
33. ड्राफ्ट विनियम में सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता को घटाकर चार दिन किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर के उन लाइसेंस सेवा क्षेत्रों को इस दायरे से बाहर रखा गया है जहां अगले निर्णय तक मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे। असम के लाइसेंस सेवा क्षेत्र को भी शामिल माना जाएगा क्योंकि इसका नाम अपवाद वाले लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों की सूची में गलती से छूट गया था। यह मुद्दा एक हितधारक ने अपनी टिप्पणी में उठाया था और इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की थी। इसलिए जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए मौजूदा प्रावधानों को छोड़कर अन्य सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता 4 दिन होगी। संशोधित प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता प्रचालक से अनुरोध प्राप्त करने के समय एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड प्रमाणित की जाएगी इसलिए 4 दिन की वैधता पर्याप्त है।

पोर्टिंग की समय-सीमाएं

34. ड्राफ्ट विनियम में कार्पोरेट श्रेणी के तहत किए गए अनुरोध को छोड़कर अंतरा-लाइसेंस सेवा क्षेत्र (अंतरा-एलएसए) के पोर्टिंग अनुरोधों के लिए 2 कार्यदिवसों की समय-सीमा का प्रावधान किया गया है। अंतरा-लाइसेंस सेवा क्षेत्र (अंतरा-एलएसए) और कार्पोरेट श्रेणी के नंबरों के सभी पोर्टिंग अनुरोधों के लिए 4 कार्यदिवसों की समय-सीमा का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त प्रावधान एमएनपी समय-सीमा प्रक्रिया की समीक्षा को केन्द्रीय निगरानी प्रणाली (सीएमएस) के कार्यान्वयन से असंबद्ध करने के लिए दूरसंचार विभाग से प्राप्त सुझाव के आधार पर किए गए हैं क्योंकि सभी एलईए को सीएमएस प्लेटफॉर्म से जुड़ने में कुछ समय लग सकता है। दूरसंचार विभाग ने भाद्विप्रा को मौजूदा प्रावधान की समीक्षा करने और केवल अंतरा-एलएसए एमएनपी अनुरोधों के मामले में दाता प्रचालक द्वारा स्वीकृति हेतु 4 कार्यदिवसों की समय-सीमा को 2 कार्यदिवस करने का सुझाव दिया है, जबकि अंतरा-एलएसए एमएनपी अनुरोधों के मामले में दाता प्रचालक द्वारा 4 कार्यदिवसों की मौजूदा समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
35. अंतरा-एलएसए और अंतरा-एलएसए के लिए अलग-अलग समय-सीमा के लाभों के बारे में ड्राफ्ट विनियम में अच्छे से स्पष्ट किया गया है और इन्हें दोहराया गया है। अंतरा और अंतरा-एलएसए पोर्टिंग अनुरोधों की अलग-अलग समय-सीमा को कार्यान्वित करने के संभावित कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए अप्रैल, 2017 से जून, 2018 की अवधि के दौरान एमएनपीएसपी से एकत्रित डाटा से पता चलता है कि अंतरा पोर्टिंग अनुरोध कुल एमएनपी अनुरोधों के लगभग 93 प्रतिशत के बराबर हैं। अंतरा-एलएसए पोर्टिंग अनुरोधों के लिए दो दिन की समय-सीमा के कार्यान्वयन पर दूरसंचार सेवा प्रदाता/एमएनपीएसपी की राय मांगने के लिए 16 अगस्त, 2018 को भाद्विप्रा में एक बैठक आयोजित की गई थी।
36. उपरोक्त मुद्दे पर कुछ हितधारक पोर्टिंग के समय में कमी के लिए प्रस्तावित बदलाव से सहमत थे। एक हितधारक ने कहा कि अंतरा के लिए दो दिन और अंतरा-एलएसए एमएनपी के लिए 4 दिन की प्रस्तावित समय-सीमा अभी भी उपेक्ष्य है और रीयल टाइम नंबर पोर्टिंग का लक्ष्य हासिल होने तक पोर्टिंग प्रक्रिया की समय-सीमा में और कमी करने के लिए इसकी नियमित आधार पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।
37. कुछ हितधारकों का यह मानना था कि एमएनपी प्रक्रिया में प्रस्तावित कमी तभी संभव हो सकती थी जब दूरसंचार विभाग से सब्सक्राइबर प्राप्ति हेतु ईकेवाईसी प्रक्रिया को हटाने का आदेश प्राप्त नहीं होता। यदि पेपर सीएफ के जरिये पहले की सब्सक्राइबर प्राप्ति प्रक्रिया दूरसंचार सेवा प्रदाता पर लगाई जाती तो इससे न केवल सेवा को एक्टीवेट करने में लगने वाला समय बढ़ता बल्कि प्राप्तकर्ता प्रचालक की ओर से कई कार्य अपेक्षित होंगे जिसमें 4 दिन से अधिक समय लगता है और इस बीच विशेष पोर्टिंग कोड समाप्त हो जाएगी। इन हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया कि अंतरा-एलएसए पोर्टिंग (अंतरा-ऑपरेटर पोर्टिंग के मामले में), समय-सीमा को घटाकर दो दिन किया जा सकता है क्योंकि पोर्टिंग एक ऑपरेटर के भीतर होनी है और ऐसे मामलों में दाता और प्राप्तकर्ता प्रचालक व्यावहारिक रूप से एक ही हैं।
38. संशोधित एमएनपी प्रक्रिया¹ में, पोर्टिंग के लिए कुल समय, कार्पोरेट मोबाइल नंबरों और अंतरा-एलएसए पोर्टिंग को छोड़कर सभी सब्सक्राइबरों के लिए कम हो जाएगा। दाता प्रचालक के डाटाबेस से जांच करके मोबाइल नंबरों के लिए एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन की जाएगी, इसलिए गैर-कार्पोरेट नंबरों के लिए मोबाइल नंबर की पोर्टिंग के चरण में दाता प्रचालक से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन और कागजी कार्य पूरा करने के लिए कुछ हितधारकों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त समय-सीमा का मुद्दा प्रासंगिक नहीं है क्योंकि पोर्टिंग का अनुरोध सभी 'अपने ग्राहक को जानें' संबंधी कार्यों को पूरा करने के बाद प्रस्तुत किया जाता है। एमएनपीएसपी केवल कार्पोरेट मोबाइल नंबरों के पोर्टिंग अनुरोधों के प्राधिकार पत्र की जांच करने के लिए दाता प्रचालक को अग्रणी करेगा।
39. प्राधिकरण द्वारा ड्राफ्ट विनियम में यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि सभी एलईए के सीएमएस से जुड़ने के बाद समय-सीमा की समीक्षा की जाएगी। अंतरा-ऑपरेटर (अंतरा-एलएसए) पोर्टिंग के मामले में समय-सीमा कम करने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण का यह मत है कि एलईए के बदलाव के कारण राज्यों के नोडल अधिकारियों द्वारा अपेक्षित स्वीकृति को दो कार्यदिवसों में जारी करना मुश्किल होगा इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, केवल अंतरा-एलएसए के पोर्टिंग अनुरोधों के लिए 2 कार्यदिवसों की पोर्टिंग समय-सीमा का प्रावधान किया गया है। अंतरा-एलएसए और कार्पोरेट श्रेणी के नंबरों के पोर्टिंग हेतु चार दिन की समय-सीमा का प्रावधान जारी रहेगा।

पोर्टिंग अनुरोध वापस लेना

40. ड्राफ्ट संशोधन में, पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत करने के 24 घंटे के भीतर सब्सक्राइबर द्वारा एसएमएस द्वारा पोर्टिंग अनुरोध वापस लेने का प्रावधान किया गया है। इस मुद्दे पर कुछ हितधारकों की यह राय है कि आमतौर पर सब्सक्राइबर पूछताछ या अपनी सेवाओं की निरंतरता के बारे में पूछने के लिए अपने

1 यह उम्मीद है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापित केन्द्रीय निगरानी प्रणाली निकट भविष्य में पूर्णतया चालू हो जाएगी और सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियां केन्द्रीकृत प्रणाली का उपयोग कर पाएंगी। बहरहाल, दूरसंचार विभाग के सुझाव के अनुसार, अंतरा और अंतरा-एलएसए पोर्टिंग की समयसीमा सीएमएस के पूर्ण कार्यान्वयन होने तक अलग-अलग रखी जाएगी।

वर्तमान ऑपरेटर (दाता प्रचालक) से संपर्क करता है इसलिए प्राप्तकर्ता प्रचालक से पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त करने के समय (तारीख और समय के साथ) की जानकारी एमएनपीएसपी द्वारा सब्सक्राइबर को दी जानी चाहिए ताकि सब्सक्राइबर इच्छुक होने पर पोर्टिंग अनुरोध को वापस लेने की सुविधा का लाभ उठा सके। हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया कि यदि सब्सक्राइबर 24 घंटे की निर्धारित समय-सीमा के बाद वापसी का अनुरोध प्रस्तुत करता है तो ऐसे मामले में एमएनपीएसपी को आवेदन पर कार्यवाही शुरू करने से पहले सब्सक्राइबर के साथ-साथ दाता प्रचालक को भी एसएमएस द्वारा सूचित करना चाहिए।

41. कुछ हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया कि सब्सक्राइबर द्वारा वापस लेने का अनुरोध करने के बाद विशेष पोर्टिंग कोड के दुरुपयोग को रोकने के लिए सब्सक्राइबर द्वारा प्राप्त किया हुआ विशेष पोर्टिंग कोड अमान्य हो जाए ताकि इसी विशेष पोर्टिंग कोड के प्रयोग से और पोर्टिंग अनुरोध न किए जा सकें। कुछ हितधारकों ने प्रस्ताव दिया कि पोर्ट वापस लेने की समय-सीमा को 24 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया जाए। वापस लेने की समय-सीमा को एमएनपीएसपी द्वारा "पोर्ट घोषणा तारीख" तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सब्सक्राइबर के लिए रद्दकरण अनुरोध भेजने के लिए समय का कोई बंधन न हो।
42. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों की जांच की है। सब्सक्राइबर और दाता प्रचालक को सूचना मुहैया कराने के संबंध में, यह प्रावधान किया गया है कि प्राप्तकर्ता प्रचालक से पोर्टिंग का अनुरोध मिलने पर एमएनपीएसपी पोर्टिंग की निर्धारित तारीख और समय की सूचना देने के लिए सब्सक्राइबर को एक एसएमएस भेजेगा। इस संदेश में सब्सक्राइबर को पोर्टिंग अनुरोध वापस लेने की 24 घंटे की समय-सीमा दी जाएगी। यदि वापस लेने का अनुरोध निष्पादित किया जाता है तो विशेष पोर्टिंग कोड अमान्य हो जाएगा। यदि वापस लेने का अनुरोध निर्धारित 24 घंटे की समय-सीमा के बाद प्राप्त होता है तो एमएनपीएसपी सब्सक्राइबर को एसएमएस द्वारा सूचित करेगा कि पोर्ट वापस लेने की समय-सीमा समाप्त हो गई है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक्टीवेशन और डि-एक्टीवेशन की तय तारीख और समय के साथ कार्यवाही की जाएगी। एमएनपीएसपी इसकी सूचना संचार के आंतरिक माध्यम के जरिये संबंधित दाता प्रचालक और प्राप्तकर्ता प्रचालक को भी देगा।

कार्पोरेट मोबाइल नंबर की पोर्टिंग

43. कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया है कि एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने से पहले बकाया भुगतान वाले कार्पोरेट कनेक्शन जांच किए जाने पर पोर्टिंग के वर्तमान 4 कार्यदिवसों से अतिरिक्त 4 दिन (विशेष पोर्टिंग कोड वैधता अवधि तक) बकाया भुगतान में वृद्धि होने की संभावना है। उन कार्पोरेट कनेक्शन के संदर्भ में, जिनके बिल सृजन करने की तारीख विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने और वास्तविक पोर्टिंग तारीख के बीच आती है, से अतिरिक्त जोखिम बढ़ेगा। हितधारक ने यह भी कहा कि कंपनी-ओन्ड-कंपनी-पेड नंबरों के मामले में बकाया भुगतान जोखिम एक व्यक्तिगत कनेक्शन की तुलना में काफी अधिक है। इसलिए दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त होने पर बकाया भुगतान की अतिरिक्त जांच की जानी चाहिए।
44. हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया कि एमएनपीएसपी को ऐसे पोर्टिंग अनुरोधों को निरस्त करना चाहिए जिनमें विशेष पोर्टिंग कोड प्रीफिक्स 'सी' के साथ सृजन की जाती है मगर प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा प्राधिकार पत्र संलग्न नहीं किया जाता है और ऐसे भी मामले में, जिनमें विशेष पोर्टिंग कोड प्रीफिक्स 'सी' के साथ नहीं है मगर प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा प्राधिकार पत्र संलग्न किया गया है।
45. एक और हितधारक ने एकल विशेष पोर्टिंग कोड के तहत कार्पोरेट पोर्टिंग को अनुमति देने का अनुरोध किया है। हितधारक ने सुझाव दिया है कि यदि एकल विशेष पोर्टिंग कोड के तहत कार्पोरेट पोर्टिंग की अनुमति नहीं दी जाती है तो कम-से-कम एक प्राधिकार पत्र के तहत केवल 50 नंबरों की सीमा को हटाया जाए।
46. दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त होने पर बकाया भुगतान की जांच करने के संबंध में हितधारक के अनुरोध के बारे में प्राधिकरण का यह मत है कि इससे पोर्टिंग प्रक्रिया के लिए जटिलताएं पैदा होंगी। बकायों की वसूली के प्रावधान और पोर्ट किए गए सब्सक्राइबर द्वारा बकाए प्राप्त नहीं होने पर संबंधित प्राप्तकर्ता प्रचालक से गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन अनुरोध प्रस्तुत करने का प्रावधान विनियमों में पहले से ही है।
47. प्राधिकरण इस पर सहमत है कि प्राधिकार पत्र के बिना प्राप्त कार्पोरेट पोर्टिंग अनुरोधों या विपरीततया: पर एमएनपीएसपी द्वारा कार्यवाही नहीं की जाएगी।
48. एकल विशेष पोर्टिंग कोड में सभी कार्पोरेट नंबरों की पोर्टिंग की अनुमति देने, जैसा कि एक हितधारक ने सुझाव दिया है, में काफी जटिलताएं हैं। इस मुद्दे पर 2013 में जारी पांचवे संशोधन अधिनियम के परामर्श के दौरान पूरी जांच की गई थी। कार्पोरेट पोर्टिंग के लिए एकल प्राधिकार पत्र में 50 मोबाइल नंबरों की मौजूदा सीमा के संबंध में प्राधिकरण ने इस सीमा को बढ़ाकर प्रति प्राधिकार पत्र 100 मोबाइल नंबर करने पर सहमति दी है।

पोस्टपेड सब्सक्राइबरों के मामले में लंबित बकायों का भुगतान

49. कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया है कि विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने के तुरंत बाद या पोर्ट वैलीडेशन तारीख पर तत्काल बिल सृजन करके बिल्ड और अन-बिल्ड प्रभागों का भुगतान करने के लिए सब्सक्राइबरों को सूचित किया जा सकता है ताकि पोर्ट आउट से पहले सब्सक्राइबर द्वारा बकायों का भुगतान किया जा सके। हितधारकों ने सुझाव दिया कि बदलते व्यवसायिक परिदृश्य और प्रौद्योगिकीय प्रगति को देखते हुए तत्काल बिलिंग को अनुमति देकर दाता प्रचालक को पोर्टिंग से पहले सब्सक्राइबरों से सभी अदत्त बकायों को लेने की अनुमति दी जा सकती है और गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है।
50. प्राधिकरण ने उपरोक्त प्रस्ताव की खुबियों और कमियों का विश्लेषण किया है और उनका यह मानना है कि पोर्टिंग से पहले अनबिल्ड उपयोग के लिए तत्काल बिल सृजन करने की अनुमति देने से सब्सक्राइबरों को सुविधा के बजाय परेशानी बढ़ जाएगी। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, पोर्टिंग के समय इस तरह के अनबिल्ड बकायों की वसूली दाता प्रचालक द्वारा मोबाइल नंबर को पोर्ट करने के बाद भी की जा सकती है। बकायों के गैर-भुगतान के परिणाम के रूप में सब्सक्राइबर गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन प्रक्रिया के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर को गंवा सकता है।
51. उपरोक्त के दृष्टिगत, पोर्ट करा चुके सब्सक्राइबरों से लंबित बकायों को जल्दी वसूल करने के लिए प्राधिकरण ने वैकल्पिक रूप से दाता प्रचालक को उसके नेटवर्क से नंबर को पोर्ट करने के तुरंत बाद बकाया बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसलिए पोर्टिंग होने के पश्चात, बिना सामान्य बिलिंग चक्र का इंतजार किए, मोबाइल नंबर पोर्ट करने की तारीख तक, अनबिल्ड राशि का बिल जारी किए जाने पर दाता प्रचालक को सब्सक्राइबर को याद दिलाने तथा बकाया वसूल करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रहेगा।

एमएनपी विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन

52. पोर्टिंग अनुरोधों को गलत तरीके से अस्वीकरण को हतोत्साहित करने और विभिन्न कार्यों को करने लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन कराने के लिए दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम (चौथा संशोधन विनियम, 2012) के माध्यम से वित्तीय अनुत्साहन के प्रावधान किए गए हैं। प्राधिकरण का यह मत है कि संशोधित विनियमों में एमएनपीएसपी के बढ़े हुए कार्यों और विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने की रूपरेखा में बदलाव के कारण दाता प्रचालक

और एमएनपीएसपी की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। संशोधित प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण है कि दाता प्रचालक द्वारा गलत अस्वीकरण और विनियम 6क के तहत निर्धारित प्रक्रिया के लिए एमएनपीएसपी द्वारा की गई क्वेरी के लिए झूठी/गलत सूचना देने को हतोत्साहित किया जाएगा। इसलिए मोबाइल सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा करने के लिए विनियमों के इस तरह के उल्लंघनों की जांच की जाएगी और यदि जरूरी हुआ तो वित्तीय अनुत्साहन लगाए जाएंगे।

53. विनियम 12 के तहत मौजूदा प्रावधान के अनुसार, दाता प्रचालक द्वारा अस्वीकरण के नमूने के विश्लेषण में ये देखा गया कि अवैध आधारों पर अस्वीकृत किए गए मामलों की संख्या काफी अधिक है। इस तरह के अस्वीकरण से दूरसंचार सब्सक्राइबर्स को भारी असुविधा हुई है। पिछले अनुभव को ध्यान में रखकर, प्राधिकरण का यह मत है कि यदि कोई एक्सेस प्रदाता (दाता प्रचालक के रूप में काम कर रहा) विनियम 6क और 12 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके लाइसेंस के नियम एवं शर्तों या अधिनियम के प्रावधानों, नियमों या विनियमों या दिए गए आदेशों या जारी निदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे पोर्टिंग के लिए अनुरोध के प्रत्येक गलत अस्वीकरण या झूठी/गलत सूचना देने के प्रत्येक मामले के लिए एक वित्तीय अनुत्साहन के रूप में एक राशि जो दस हजार रुपये से अनधिक नहीं होगी, या जैसा भी प्राधिकरण निदेश दे, का भुगतान करना होगा।
54. प्रस्तावित वित्तीय अनुत्साहन के मुद्दे पर एक हितधारक ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण को जानबूझ कर किए गए उल्लंघन और सिस्टम की खराबी के कारण तकनीकी त्रुटि को अलग-अलग करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिस्टम की खराबी के परिणामस्वरूप होने वाली त्रुटि के लिए दाता प्रचालक पर दंड न लगाया जाए।
55. एक हितधारक ने उल्लेख किया कि प्राधिकरण ने एमएनपीएसपी पर लागू जुर्माने का प्रस्ताव किया है जो अनुचित रूप से कठोर और दंडात्मक हैं। हितधारक ने जुर्माने के औचित्य का प्रस्ताव करते हुए कहा है कि प्रतिशत आधारित सेवा स्तर समझौता (एसएलए) बताया जाए ताकि जुर्माना तभी आकलित हो जब रिपोर्टिंग अवधि में विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोध के नियत प्रतिशत से अधिक समय पर सृजन नहीं होते हैं। इसे प्राधिकरण के लिए मासिक मानक रिपोर्ट का भाग बनाया जा सकता है और यथा समय जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना उदार होना चाहिए और इसका आकलन अधिक महत्वपूर्ण हो यदि क्रमागत महीनों में मामलों का दोहराव हो। इसके अतिरिक्त, एसएलए को प्रश्नागत पक्ष के लिए विशिष्ट बनाने के लिए इसे परिभाषित करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए।
56. प्राधिकरण इस सुझाव पर सहमत है कि एमएनपीएसपी और दूरसंचार सेवा प्रदाता, दोनों पर लागू सेवा गुणवत्ता प्रणाली के जरिये तकनीकी त्रुटि के मुद्दों/घटनाओं की निगरानी की जा सकती है। प्राधिकरण एमएनपीएसपी और एक्सेस प्रदाताओं द्वारा पालन किए जाने हेतु उचित सेवा गुणवत्ता मानदंड अलग से जारी करेगा। एमएनपी की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए मानदंड या एसएलए मानदण्ड बनाए जा सकते हैं और एमएनपीएसपी और एक्सेस प्रदाताओं की ओर से उल्लंघन एवं विचलन के लिए वित्तीय अनुत्साहन लगाए जाएंगे। प्राधिकरण ऐसे मानक परिभाषित करने के लिए हितधारकों से अलग से परामर्श करेगा।

विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण के दौरान सब्सक्राइबर संबंधी मुद्दों को देखना

57. विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण के दौरान, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पात्रता की सभी शर्तों की जांच करने के बाद प्रत्येक अनुरोध के लिए विशेष पोर्टिंग कोड सृजित किया जाए। यदि सब्सक्राइबर का पोर्ट का अनुरोध विशेष पोर्टिंग कोड के लिए अर्हक नहीं है या उस समय कोई तकनीकी समस्या है तो इसकी उचित और समय पर सूचना जरूर दी जाए। यह पूरी प्रक्रिया लाइसेंसर और भादूविप्रा की जांच के अधीन है। विशेष पोर्टिंग कोड प्राप्त करने और उसका नंबर पोर्ट करने की प्रक्रिया के दौरान सब्सक्राइबर को अपने पोर्टिंग अनुरोध पर कार्यवाही के दौरान कुछ क्वेरी/मामलों का सामना कर पड़ सकता है।
58. सब्सक्राइबर्स के मुद्दों/शिकायतों को संभालने के संबंध में एक हितधारक ने पोर्टिंग प्रक्रिया की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने, फर्जी पोर्टिंग पर रोक लगाने, सब्सक्राइबर्स की शिकायतों का समाधान करने के लिए एमएनपीएसपी की जवाबदेही बढ़ाने की मांग की है। हितधारक ने प्रस्ताव किया है कि पोर्टिंग अनुरोधों के चरणों को पूरा करने के बारे में सब्सक्राइबर को सूचना देने, अनुरोध की स्थिति निर्दिष्ट करने (स्वीकृत है या अस्वीकृत), सब्सक्राइबर्स की एमएनपी संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने की जिम्मेदारी एमएनपीएसपी की होनी चाहिए।
59. एक और हितधारक ने कहा कि एमएनपीएसपी को एसएमएस के माध्यम को छोड़कर सब्सक्राइबर्स से सीधे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे अरब से अधिक सब्सक्राइबर्स से कई भाषाओं में सीधे बात करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। ऑपरेटरों के पास अपरिमित संसाधन और कॉल सेंटर हैं और वे इस काम को कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। हितधारक ने यह भी कहा है कि यदि एमएनपीएसपी को सब्सक्राइबर्स के संचार का संचालन करना है तो उन्हें मुहैया कराए गए मूल्य में अत्यधिक वृद्धि करनी होगी। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ हितधारकों ने प्रस्ताव दिया है कि एमएनपीएसपी एक पोर्टल मुहैया करा सकते हैं, जिसमें दाता प्रचालक विशेष पोर्टिंग कोड, पोर्टिंग आदि की स्थिति जान सकते हैं।
60. प्राधिकरण ने हितधारकों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों का विश्लेषण किया और उनका यह मत है कि सब्सक्राइबर्स को एमएनपीएसपी से सीधे बात करने की जरूरत नहीं है, इसके दो कारण हैं, पहला, सब्सक्राइबर अपने सेवा प्रदाता से बात करने से परिचित होते हैं, जिनके पास सब्सक्राइबर्स की शिकायतों का प्रभावी तरीके से समाधान करने के लिए अपने संसाधन और कॉल सेंटर पहले से होते हैं। इसके विपरीत, सब्सक्राइबर्स की पूछताछ और कॉल को संभालने के लिए एमएनपीएसपी को अपनी ओर से इन संसाधनों की व्यवस्था को दोहराना होगा। दूसरा, विशेष पोर्टिंग कोड का सृजन और आवंटन करने से पहले दाता प्रचालक के डाटाबेस से की गई जांच के जवाब में एमएनपीएसपी को केवल 'हां' या 'नहीं' में सूचना प्राप्त करनी होगी, और एमएनपीएसपी के पास सब्सक्राइबर के विभिन्न आधारों और अनुरोध को अस्वीकृत करने के विशिष्ट कारणों के बारे में कोई दूसरी जानकारी नहीं होगी। इसलिए कॉल और पूछताछ संभालने के लिए एमएनपीएसपी को अधिदेश के देने के स्थान पर सब्सक्राइबर्स की पूछताछ और शिकायतों का समाधान करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता बेहतर स्थिति में होगा।
61. हालांकि प्राधिकरण का मानना है कि सब्सक्राइबर को असुविधा नहीं होनी चाहिए और वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके नियत सूचना प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए। इसलिए एमएनपीएसपी द्वारा प्रबंधित वेब पोर्टल और/या एप, जो दाता प्रचालक और सब्सक्राइबर (ओटीपी आधारित अधिप्राप्त) को सुलभ है, पोर्टिंग की प्रगति या अस्वीकरण, यदि कोई हो, के बारे में सूचना सब्सक्राइबर को देने में उपयोगी होंगे। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाता या एमएनपीएसपी को मिलने वाली पूछताछ/शिकायतों में कमी आएगी।

विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण तथा सब्सक्राइबर को कम्युनिकेशन भेजने से जुड़ी लागतें

62. ऊपर बताए गए विषय पर एक हितधारक ने कहा है कि ड्राफ्ट विनियम के अनुसार, विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने के लिए एमएनपीएसपी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार पक्ष के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने के लिए लागत में वृद्धि की संभावना हो सकती है। हितधारक ने यह भी कहा है कि वर्तमान में लगभग 2 विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोध पर 1 पोर्ट अनुरोध का अनुपात है। इसलिए पोर्टिंग हेतु अनुरोध को संसाधित करने के अलावा संसाधित किए गए प्रत्येक विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोध के लिए एमएनपीएसपी को उचित टैरिफ का भुगतान किया

जाना चाहिए। यदि प्राधिकरण यह नियम बनाता है कि सफल पोर्ट के टैरिफ में विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने की लागत भी शामिल की जानी चाहिए तो तदनुसार शुल्क समायोजित किया जाना चाहिए।

63. संबंधित लागतों के पहलुओं पर प्राधिकरण का यह मत है कि प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभारों की अलग से समीक्षा की जाएगी और इन प्रभारों में एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने की लागत और विभिन्न चरणों में एसएमएस भेजने की लागत भी शामिल की जाएगी। इसके लिए हितधारकों से अलग से परामर्श किया जाएगा।

संशोधन के कार्यान्वयन की समयावधि

64. ड्राफ्ट संशोधन विनियमों में, कार्यान्वयन हेतु सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के बाद छह माह का समय निर्धारित किया गया है। एक हितधारक ने अनुरोध किया है कि किए जा रहे बदलावों के महत्व, कई संस्थाओं द्वारा बदलाव करने के कारण कठोर परीक्षण की आवश्यकता है, इसलिए प्राधिकरण को विस्तार के लिए कुछ पक्षों के द्वारा समय बढ़ाने के अनुरोधों के लिए तैयार रहना चाहिए।
65. एक और हितधारक ने कहा है कि सरकारी राजपत्र में विनियम के प्रकाशन की तारीख के बाद, उद्योग के पास बदलावों को लागू करने के लिए 6 माह का समय होगा, जिसके बाद, नया विनियम लागू हो जाएगा। नई एमएनपी प्रक्रिया को लागू करने के लिए एमएनपीएसपी और दूरसंचार सेवा प्रदाता को नए हार्डवेयर खरीदने होंगे और अपने संबंधित एप्लिकेशन में बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर में बदलाव करने होंगे। यह अनुमान है कि नए विनियम के लागू होने से पहले प्रत्येक ऑपरेटर के साथ एंड-टू-एंड प्रोसेस फ्लो टेस्टिंग भी अपेक्षित होगी।
66. प्राधिकरण का यह मत है कि संशोधन विनियमों को लागू करने के लिए छह माह का समय पर्याप्त है।

प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के मामले में अव्ययित शेष को वापस करना

67. पोर्टिंग की सामान्य परिस्थितियों में, वर्तमान विनियम, पोर्टिंग के समय प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के मामले में अव्ययित शेष को वापस नहीं करता है। प्राधिकरण को सब्सक्राइबर्स से इस मुद्दे पर असंख्य पत्र प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा, हाल के मामलों में कुछ ऑपरेटरों की सेवाएं शॉर्ट नोटिस पर या अचानक बंद कर दी गई हैं। इस मुद्दे पर कई हितधारकों ने 6 अप्रैल, 2018 को प्राधिकरण द्वारा जारी परामर्श पत्र के जवाब में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की थी। कुछ हितधारक पोर्टिंग पर अव्ययित प्रीपेड शेष को वापस करने के लिए प्रावधान करने के पक्ष में थे। एक हितधारक ने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और बैंक खाते के माध्यम से रिफंड का सुझाव दिया था। जबकि कई हितधारकों ने इस पर चिंता प्रकट की थी कि इसको लागू करने में शामिल प्रशासनिक लागत अधिकांश प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के मामले में अव्ययित शेष से अधिक होगी।
68. हितधारक ने यह भी कहा कि मौजूदा टैरिफ प्लान और फ्री कॉल्स और कुछ जीबी डेटा प्रतिदिन के साथ मौजूदा विकल्पों की संरचना के कारण सब्सक्राइबर्स के लिए मुख्य खाते में प्रीपेड बैलेंस रखने की आवश्यकता में काफी कमी आई है। हितधारकों का यह भी मत था कि पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा के अलावा, टॉक टाइम बैलेंस को समान मोड्रिक मूल्य में नहीं बदला जा सकता जो पोर्टिंग के समय सब्सक्राइबर को वापस किया जा सकता है।
69. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों की टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकरण का यह मत है कि सामान्य परिस्थितियों में सब्सक्राइबर द्वारा जानबूझ कर कराए गए पोर्टिंग के मामले में सब्सक्राइबर को अपना प्रीपेड मोबाइल नंबर को पोर्ट करने का निर्णय लेने से पहले अपने अव्ययित शेष को उपयोग करना होगा। साधारण पोर्टिंग प्रक्रिया के अलावा, कतिपय असाधारण परिस्थितियां जैसे सेवा का अकस्मात बंद होना, लाइसेंस/स्पेक्ट्रम को वापस करना आदि देखने में आई हैं। सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा करने के लिए प्राधिकरण ने प्रीपेड मोबाइल सब्सक्राइबर्स के अव्ययित शेष को वापस करने के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं को निदेश जारी किए थे। प्राधिकरण का यह मानना है कि किसी ऐसी अप्रत्याशित स्थिति, जिसमें सब्सक्राइबर को उसकी इच्छा के खिलाफ पोर्ट आउट के लिए विवश किया जाता है, का समाधान प्रचलित प्रवृत्ति के अनुसार समय-समय पर निदेश जारी करके किया जाएगा।

गैर भुगतान डिस्कनेक्शन अनुरोध के तहत मोबाइल नंबर को फिर से कनेक्ट करना

70. परामर्श पत्र के जरिए, ऐसे मामलों में जहां सब्सक्राइबर डिस्कनेक्शन के बाद (मगर साठ दिन की अवधि समाप्त होने से पहले) भुगतान कर देता है, तो प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा एमएनपीएसपी को प्रस्तुत गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन (एनपीडी) अनुरोध के बाद भी मोबाइल नंबर को फिर से चालू करने के मुद्दे को उठाया गया था। मौजूदा एमएनपी विनियम में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामले देखने में आए हैं जिनमें सब्सक्राइबर वास्तविक दिक्कतों के चलते नोटिस की अवधि के भीतर भुगतान करने में समर्थ नहीं हो सके हैं और वे अपना मोबाइल नंबर वापस लेने के लिए पूरी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। मगर मौजूदा प्रक्रिया में वे अपना मोबाइल नंबर वापस पाने में असमर्थ हैं और उनका नंबर, नंबर रेंज धारक को वापस कर दिया जाता है। मौजूदा परिदृश्य में इस तथ्य को देखते हुए कि मोबाइल नंबर काफी अधिक महत्वपूर्ण बन गया है, जिसको गंवाने से गंभीर व्यक्तिगत और वित्तीय परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सब्सक्राइबर के नंबर को पुनः एक्टिवेट करने के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं।
71. हितधारक इस पर सहमत हैं कि नंबर रेंज धारक को नंबर वापस नहीं करने के समय तक, दाता प्रचालक और प्राप्तकर्ता प्रचालक के साथ सब्सक्राइबर का सत्यापन करने और 60 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान प्राप्त होने पर एमएनपीएसपी की मदद द्वारा नंबर को फिर से प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा एक्टिवेट किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता प्रचालक के अनुरोध पर एमएनपीएसपी को वापसी प्रक्रिया को समाप्त करना होगा। प्राधिकरण का यह मत है कि यह व्यवस्था प्राप्तकर्ता प्रचालक और दाता प्रचालक, दोनों के लिए लाभप्रद होगी, क्योंकि दाता प्रचालक पोर्ट करा चुके सब्सक्राइबर से अपने बकायों को वसूल करने और प्राप्तकर्ता प्रचालक सब्सक्राइबर को अपना बनाए रखने में समर्थ होता है।

एमएनपीएसपी द्वारा मुहैया कराई गई सहायक सेवाओं के प्रभार

72. परामर्श प्रक्रिया में सहायक सेवाओं के प्रभार का मुद्दा हितधारकों की टिप्पणी के लिए शामिल गया था। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया था कि ये प्रभार नंबर वापस करने, डाटाबेस का डाउनलोड, पोर्ट को रद्द करना और सब्सक्राइबर रिकनेक्शन कार्यों के लिए इसके संसाधनों के प्रयोग के लिए अतिरिक्त सेवाएं मुहैया कराने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को दिए जाने चाहिए। तदनुसार, निम्नलिखित कार्य करने के लिए एमएनपीएसपी को देय सहायक प्रभारों के लिए विनियम में प्रावधान किया गया है:

क) गैर-भुगतान सहित किसी अन्य कारण से डिस्कनेक्शन के बाद नंबर रेंज धारक को मोबाइल नंबर वापस करने को सुगम बनाने के लिए 'नंबर वापसी प्रभार' के लिए प्रावधान किया गया है।

ख) पहुंच प्रदाता द्वारा नंबर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस डाउनलोड करने के लिए 'डाउनलोड प्रभार' का प्रावधान किया गया है।

- ग) दाता प्रचालक के सब्सक्राइबर के 'पोर्ट वापस लेने' के अनुरोध के निष्पादन के लिए 'पोर्ट रद्दकरण प्रभार' का प्रावधान किया गया है।
- घ) प्राप्तकर्ता प्रचालक के नेटवर्क पर पोर्ट करा चुके सब्सक्राइबर को फिर से कनेक्ट करने को सुगम बनाने के लिए 'सब्सक्राइबर रिकनेक्शन प्रभार' का प्रावधान किया गया है।
- ड.) पोस्टपेड सब्सक्राइबर, जिसने अपना नंबर पोर्ट कराने के बाद दाता प्रचालक के बकायों का भुगतान नहीं किया है, के मोबाइल नंबर के डिस्कनेक्शन को सुगम बनाने के लिए 'गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन' प्रभार के लिए प्रावधान किया गया है।
73. प्रारूप विनियम में किए गए ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के प्रत्युत्तर में कुछ हितधारकों ने एमएनपीएसपी को देय सहायक प्रभारों का समर्थन किया है, एक हितधारक ने कहा है कि वह सहायक सेवा प्रभार को शामिल करने के मामले पर सहमत है। दूसरे हितधारक ने सुझाव दिया कि गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन एमएनपीएसपी द्वारा मुहैया कराई गई सेवा है और दाता प्रचालक द्वारा देय 'गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन प्रभार' शामिल किए जाने चाहिए।
74. जिन हितधारकों ने सहायक सेवा प्रभार लेने का समर्थन नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि 4 रु. प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार, जो एमएनपीएसपी प्राप्तकर्ता प्रचालक से लेता है, में सभी लागतें शामिल हैं। प्राप्तकर्ता प्रचालक और दाता प्रचालक द्वारा क्रमशः रिकनेक्शन या रद्दकरण के मामले में, वर्तमान में सब्सक्राइबरों से प्रभार नहीं लिए जा रहे हैं, इसलिए एमएनपीएसपी को इन कार्यों के लिए एक्सेस प्रदाताओं से प्रभार लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
75. हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया कि मोबाइल नंबर का रिकनेक्शन पूरी तरह से सब्सक्राइबर और दूरसंचार सेवा प्रदाता के बीच का मामला है, जिसके लिए केवल दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा पुनः प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है और उन्हें इसमें एमएनपीएसपी के लिए कोई भूमिका नजर नहीं आती है, इसलिए एमएनपीएसपी को रिकनेक्शन प्रभार देने की कोई औचित्य नहीं है।
76. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों की जांच की है। प्राधिकरण का यह मत है कि सहायक सेवाओं के लिए प्रावधान विनियम में बना रहेगा, बशर्ते, प्रभारों की वास्तविक राशि को परिभाषित करने के समय परामर्श किया जाएगा अन्यथा इनको प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभारों के रूप में शामिल कर लिया जाएगा।

एस. के गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./415/18]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2018

Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018 (9 of 2018)

No. 116-6/2017-NSL-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36, read with sub-clauses (i), (iii) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018 (9 of 2018).
(2) These regulations shall come into force after six months from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 2 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) (hereinafter referred to as principal regulations),--
 - (a) in clause (a), after the words, "Unified Access Service license or Unified license (access service) or unified license having authorization to provide access service", the words "or Unified License (Virtual Network Operator) having authorization to provide access service" shall be inserted;
 - (b) after clause (ba), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(bb) ancillary service charge means the charge paid to the Mobile Number Portability Service provider at the rate specified by the Authority from time to time and includes the charges to be paid by --

 - (i) the Number Range Holder for facilitating return of the mobile number after disconnection due to any reason including non-payment;
 - (ii) the Access Provider for downloading the Number Portability database;
 - (iii) the Donor operator for execution of porting withdrawal request of its subscriber;
 - (iv) the Recipient Operator for facilitation of reconnection of ported subscriber in its network;
 - (v) the Donor Operator for facilitation of disconnection of the mobile number of the postpaid subscriber who has not cleared the dues of the Donor Operator after porting his number;

- (c) in clause (e), for the words, “a Cellular Mobile Telecom Service provider or Unified Access Service provider” the words, “an Access Provider” shall be substituted;
- (d) in clause (jb) for the words “in an MNP Zone” the words “for the licensed service area” shall be substituted;
- (e) after clause (jb), the following clause shall be inserted namely:-
 "(jc) “Network Service Operator” means the operator defined under the Unified License (Virtual Network Operator) which owns the telecom core network and provides core network service to the Virtual Network Operator to connect different parts of the access network and gateway to other networks;”;
- (f) in clause (n) for the words “processing the porting request” the words “each successful porting” shall be substituted;
- (g) in clause (t), for the words, “by an Access Provider”, the words, “by the Mobile Number Portability Service Provider of the Zone to which the mobile number belongs to” shall be substituted;

3. For regulation 5 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:

“5. Obligation to set up mechanism for allocation of unique porting code.-- (1) Every Access Provider shall set up, in its mobile network, a mechanism for the purpose of receiving Short Message Service (SMS) from its subscribers requesting for a unique porting code and forwarding the same to the Mobile Number Portability zone to which the mobile number belongs;

(2) Every Mobile Number Portability service provider shall set up, in its network, a mechanism for the purpose of--

- (a) receiving requests for unique porting code forwarded by the Donor Operator as per sub-regulation (1) of regulation 5;
- (b) checking from the database of the Donor Operator through query response mechanism, on the applicable grounds of rejection of request for Unique porting code;
- (c) allocating a unique porting code for each such request and communicating it to the subscriber forthwith through Short Message Service; and
- (d) retaining such unique porting code on its records for the purpose of verification of the porting request of such subscriber to be received from the Recipient Operator.

Provided that the Mobile Number Portability service provider shall -----

- (a) identify and allot a distinct identification code denoted with prefix ‘C’ for the request received from the distinct corporate mobile numbers; and
- (b) in case of a request for simultaneous porting of more than one corporate mobile numbers, allocate separate unique porting code for each corporate mobile number.”

4. In regulation 6 of the principal regulations, after regulation 6, the following regulations shall be inserted namely:-

“6A. Process to be performed by Mobile Number Portability Service provider before allocating unique porting code.--(1) Upon receipt of the request for unique porting code, the concerned Mobile Number Portability Service provider shall check the following conditions from its database whether:-

- (a) the mobile number has been ported earlier and, if so, a period of ninety days has not elapsed from the date of its last porting;
- (b) porting request is already in process for the same mobile number; and
- (c) unique porting code has already been issued and not expired yet.

(2) Where Mobile Number Portability Service provider finds that the clause (a) or (b) or (c) mentioned in sub-regulation (1) are applicable, the Mobile Number Portability Service provider shall not generate unique porting code and shall communicate the reason of non-generation of unique porting code to the subscriber through SMS.

(3) Where Mobile Number Portability Service provider finds that the clause (a) and (b) and (c) mentioned in sub-regulation (1) are not applicable, it shall check immediately on real time basis from the database of Donor Operator whether:-

- (a) the number is a Corporate mobile number;
- (b) there are outstanding payments due from the post paid subscriber by way of pending bill, issued as per the normal billing cycle but before the date of request for unique porting code;

- (c) the porting request has been made before the expiry of a period of ninety days from the date of activation of a new connection;
- (d) a request for change of ownership of mobile number is under process;
- (e) the mobile number sought to be ported is sub-judice;
- (f) porting of the mobile number has been prohibited by a court of law;
- (g) there are subsisting contractual obligations in respect of which an exit clause has been provided in the subscriber agreement but the subscriber has not complied with such exit clause;

(4) The Donor Operator shall ensure that its query response mechanism provides the response, as sought by the Mobile Number Portability Service provider under sub-regulation (3) on real time basis.

(5) The Mobile Number Portability Service provider shall retain the information obtained by it under sub-regulation (3) for taking necessary action, on receipt of the porting request of the subscriber, from Recipient Operator.

(6) If the Mobile Number Portability Service provider finds that the request of the subscriber is not covered under the grounds contained in the clauses (b) to (g) of sub-regulation (3), it shall allocate unique porting code to the subscriber and communicate the same to the subscriber through SMS:

Provided that the unique porting code shall be prefixed by 'C' for corporate mobile number.

(7) If the Mobile Number Portability Service provider is not able to check the information from the database of the Donor Operator, as provided in the sub-regulation (3), for any technical reason, it shall send an SMS to the subscriber acknowledging his request for unique porting code informing him that delivery of unique porting code is delayed due to technical reason and the same shall be delivered shortly:

Provided that where Mobile Number Portability Service provider finds that unique porting code cannot be generated due to technical issues, it shall immediately send alert message to the Donor Operator raising the docket for such technical issue and shall again query the database of the Donor Operator immediately on resolution of technical issues.

(8) When any one or more of the conditions contained in clauses (b) to (g), provided under sub-regulation (3) of regulation 6A, are applicable for the mobile number under porting, the Mobile Number Portability Service provider shall not issue unique porting code to the subscriber and shall inform the mobile subscriber through SMS, the reasons for non-generation of unique porting code and retain such records for a minimum period of six months."

5. For regulation 8 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"8. Action by Recipient Operator.-- (1) The Recipient Operator shall, upon receipt of the porting request from a subscriber, ask him to send a message through SMS to a specified Short Code of the Donor Operator from the mobile number of the subscriber, which is sought to be ported.

(2) Upon receipt of the unique porting code from the Mobile Number Portability Service provider, the subscriber shall incorporate the same in the porting request form.

(3) The Recipient Operator shall, upon receipt of the porting request from the subscriber alongwith unique porting code allocated to the mobile number, verify the Customer Acquisition Form to ensure that it is accompanied by all the documents specified in regulation 7.

(4) The Recipient Operator shall, record in the Customer Acquisition Form that he has seen the subscriber and verified his documents with their respective originals and found them to be in order.

(5) The Recipient Operator shall, within a period of twenty four hours, forward the mobile number, the corresponding unique porting code and the date on which porting request is made by the subscriber, to the Mobile Number Portability Service provider of MNP zone to which the mobile number range holder of number under porting belongs and also send a SMS to the subscriber, as soon as the port request is initiated, informing him about submission of his request for porting.

(6) In case of corporate mobile number, the Recipient Operator shall also forward to the Mobile Number Portability Service provider of MNP zone to which the mobile number range holder of the number under porting belongs, a scanned copy of the authorisation letter issued by the authorized signatory permitting the porting of such mobile number:

Provided that for the corporate mobile number, the time period for forwarding the mobile number etc. to the Mobile Number Portability Service provider shall be forty eight hours from the receipt of porting request:

Provided further that forwarding of a copy of authorisation letter permitting porting of more than one and maximum upto hundred mobile numbers, in case of corporate mobile number, shall be sufficient for the purpose of sub-regulation (6):

Provided also that in calculating the period of twenty four hours specified in sub-regulation (6) and forty eight hours specified in second proviso, the intervening Sundays and Public Holidays declared under the Negotiable Instrument Act, 1881 (26 of 1881) shall be excluded.

(7) The Recipient Operator shall be liable to pay Per Port Transaction charge for each successful porting of the mobile number to the Mobile Number Portability Service provider:

Provided that the Recipient Operator shall be liable to comply with the Quality of Service parameters, as specified by the Authority from time to time.”

6. For regulation 9 of the principal regulations, the following regulations shall be substituted, namely:-,

“9. Action by Mobile Number Portability Service provider.-- (1) Upon receipt of the request for unique porting code, the concerned Mobile Number Portability Service provider shall check from its database whether:-

- (a) the mobile number has been ported earlier and, if so, a period of ninety days has not elapsed from the date of its last porting;
- (b) porting request is already in process for the same mobile number;
- (c) unique porting code has already been issued and not expired yet.
- (2) Where Mobile Number Portability Service provider finds that the conditions (a) or (b) or (c) under sub-regulation (1) are applicable, it shall not generate unique porting code and shall communicate the reason of non-generation of unique porting code to the subscriber through SMS.
- (3) Where Mobile Number Portability Service provider finds that the conditions (a) and (b) and (c) under sub-regulation (1) are not applicable, it shall check for the conditions (a) to (g) contained in sub-regulations (3) of regulation 6A.
- (4) If the Mobile Number Portability Service provider finds that the request of the subscriber is not covered under the grounds contained in clauses (b) to (g) of sub-regulation (3) of regulation 6A, it shall allocate unique porting code to the subscriber and communicate the same to the subscriber through SMS.
- (5) If the Mobile Number Portability Service provider is not able to check the information from the database of the Donor Operator, as provided in the sub-regulation (3) of regulation 6A, for any technical reason, it shall send an SMS to the subscriber acknowledging his request for unique porting code and informing him that delivery of unique porting code is delayed due to technical reason and the same shall be delivered shortly:

Provided that where Mobile Number Portability Service provider finds that unique porting code cannot be generated due to technical issues, it shall immediately send alert message to the Donor Operator raising the docket for such technical issues and shall again query the database of the Donor Operator immediately on resolution of technical issues.

- (6) When any of the conditions contained in clause (b) to (g) of sub-regulation (3) of regulation 6A are applicable for the mobile number under porting, the Mobile Number Portability Service provider shall not issue unique porting code to the subscriber and shall inform the subscriber through SMS, the reasons for non-generation of unique porting code and retain such records for a minimum period of six months.
- (7) Upon receipt of the porting request from the Recipient Operator, the Mobile Number Portability Service provider shall verify whether:-
 - (a) porting request is not in process for the same mobile number;
 - (b) unique porting code received along with the porting request matches with the unique porting code generated from its database for the mobile number under porting;
 - (c) unique porting code is valid on the date of receipt of porting request.
- (8) Where any of the conditions contained in clauses (a), (b) and (c) under sub-regulation (7), is not affirmative, the Mobile Number Portability Service provider shall reject the current request for porting and communicate such rejection to the Recipient Operator and the concerned subscriber along with the reasons of such rejection.

- (9) Upon successful validation of the conditions contained in clauses (a), (b) and (c) under sub-regulation (7), the Mobile Number Portability Service provider shall:-
- (a) in all cases except corporate mobile numbers, schedule and forthwith forward such request to Donor Operator for porting on completion of two working days for intra-licensed service area porting requests and on completion of four working days for all inter-licensed service area porting requests and inform the subscriber, through SMS, the porting schedule and the port withdrawal window available to him for twenty four hours from the time of receipt of porting request;
 - (b) for the corporate mobile numbers, where the unique porting code is prefixed with 'C', forthwith, forward the details of such request, along with scanned copy of the authorization letter received from the Recipient Operator, to the Donor Operator for clearance of its porting and inform the subscriber through SMS, the port withdrawal window available to him for twenty four hours from the time of receipt of porting request;
 - (c) upon clearance of the porting request made under the clause (b) of sub-regulation (9) of the regulation by Donor Operator, within the time limits as specified in regulation 10, schedule the porting within the next thirty six hours and inform the subscriber through SMS;
 - (d) upon non-clearance of the porting request made under the clause (b) of sub-regulation (9) of the regulation by Donor Operator, inform the subscriber through SMS the reasons for rejection of such porting request and retain the records for a minimum period of twelve months;
 - (e) for the porting request made under the clause (b) under sub-regulation (9) of regulation 9, within the time limits as specified in regulation 10, in case no response is received from Donor Operator on the porting request, schedule the porting within the next thirty six hours and inform the subscriber through SMS:

Provided that while calculating two working days and four working days, respectively, for intra-licensed service area porting requests and inter-licensed service area porting requests, intervening Sundays and public holidays declared under the Negotiable Instrument Act., 1881 (No. 26 of 1881) shall be excluded:

Provided further that for the cases where unique porting code has been generated with prefix 'C' but authorization letter is not forwarded by recipient operator alongwith the porting request and also in the cases wherein the unique porting code is not prefixed with 'C' but the authorization letter is forwarded by recipient operator, no action on such requests shall be taken by Mobile Number Portability Service provider and it shall inform the subscriber and recipient operator accordingly:

Provided also that the Mobile Number Portability Service provider shall be liable to comply with the Quality of Service parameters, as specified by the Authority from time to time."

7. For regulation 10 of the principal regulations the following regulation shall be substituted, namely:-

"10. Action by Donor Operator.-- (1) The Donor Operator shall establish a query response mechanism in its network to enable the Mobile Number Portability Service provider to access the database of the Donor Operator on real time basis to query the conditions listed in clauses (a) to (g) under sub-regulation (3) of regulation 6A.

(2) Upon receipt of the details of porting request under the clause (b) of sub-regulation (9) of regulation 9, the Donor Operator shall, within four working days, verify such details and communicate to the Mobile Number Portability Service provider, where it finds that the porting request is covered under the ground (i) specified for corporate mobile number under regulation 12, that -

- (a) it has objection to the porting of the mobile number from its network; or
- (b) it has no objection for clearance of porting request of the mobile number:

Provided that while calculating four working days as specified in this sub-regulation, intervening Sundays and public holidays declared under the Negotiable Instrument Act., 1881 (No. 26 of 1881) shall be excluded:

Provided further that the Donor Operator shall be liable to comply with the Quality of Service parameters, as specifies by the Authority from time to time.

8. In regulation 11 of the principal regulations ---

- (a) in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) where the Donor Operator has indicated the ground of rejection of the porting request under the clause (a) of sub-regulation (2) of regulation 10, forthwith communicate the ground of rejection to the mobile subscriber through SMS and send a copy for information to the Recipient Operator."

- (b) after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(7a) The Mobile Number Portability Service provider shall, on receipt of request for download of Number Portability Database from Access Providers, other than new operators, permit such downloads from its system and Access Provider shall pay for the charges for such download to the Mobile Number Portability Service provider at the rate specified by the Authority from time to time.”

9. In regulation 12 of the principal regulations-

(a) clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) & (j) shall be deleted;

(b) in first proviso after clause (j), for the words, “any grounds specified in clause (a) to (j)” the words, “ground specified in clause (i)” shall be substituted;

(c) in second proviso after clause (j), for the words, “clause (h) and (i)” the words, “clause (i)” shall be substituted;

10. For regulation 13 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“13. Withdrawal of porting request. – (1) A subscriber may withdraw the porting request by informing the Mobile Number Portability Service Provider through SMS to the specified Short Code, within the twenty four hours of withdrawal window as communicated by Mobile Number Portability Service provider.

(2) Where the Mobile Number Portability Service provider finds that the request for withdrawal has been received from the subscriber within twenty four hours of submitting of porting request to Mobile Number Portability Service provider by the Recipient Operator, it shall terminate the porting, invalidate the unique porting code for future porting, and shall inform Donor Operator, Recipient Operator and subscriber; provided that Donor Operator shall be liable to pay charges for such cancellation to the Mobile Number Portability Service provider at the rate specified by the Authority from time to time.

(3) In case the Mobile Number Portability Service provider receives the request for withdrawal of the porting after twenty four hours of submitting of porting request to Mobile Number Portability Service provider by the Recipient Operator, it shall inform the subscriber through SMS that the time for withdrawal of the porting request has expired and shall proceed with the scheduled date and time of de-activation and activation as per clause (a), (c) and (e) of the sub-regulation (9) of regulation 9.”

11. In regulation 14 of the principal regulations, in sub-regulation (5), after the words, “the details of such outstanding bills”, and before the words, “to the Recipient Operator”, the words, “including date of the bill, last date of payment, date of the notice and period of notice given to the subscriber.” shall be inserted.

12. In regulation 15 of the principal regulations,---

(a) in sub-regulation (1) after the words “Per Port Transaction charge” and before the words “at the rate as specified”, the words “and subscriber reconnection charge” shall be inserted;

(b) in sub-regulation (4), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that in case subscriber makes the payment, referred in the first proviso, and furnishes evidence of such payment to Recipient Operator within sixty days of its disconnection, the services of the subscriber shall be restored immediately and Recipient Operator shall inform the Mobile Number Portability Service provider of such restoration and recall its request for reversal of such mobile number to its Number Range Holder.”

13. In regulation 16 of the principal regulations,---

(a) in sub-regulation (2), after the words, “purpose of porting” and before the words, “and dipping” the words “, allocating and verifying the unique porting code” shall be inserted;

(b) after sub-regulation (3), following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(3) (a) The Mobile Number Portability Service provider shall generate reports regarding the number of requests received for unique porting code from the mobile subscribers, the number of unique porting code successfully allocated and the number of requests where no response or delayed response was received from the Donor Operator or any other reports required by the Authority from time to time.”;

(c) after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(5a) The Mobile Number Portability Service provider shall send bills along with the relevant details of charges for facilitation of reconnection of ported subscriber in its network to the concerned Recipient Operator on a monthly basis and shall deliver such bills to the concerned Recipient Operators for each month before the tenth day of the following month or at such periodic intervals and within such time limits, as may be mutually agreed upon.

- (5b) The Mobile Number Portability Service provider shall send bills along with the relevant details of charges for downloading the Number Portability Database to the concerned Access Provider on a monthly basis and shall deliver such bills to the concerned Access Provider for each month before the tenth day of the following month or at such periodic intervals and within such time limits as may be mutually agreed upon.
- (5c) The Mobile Number Portability Service provider shall send bills along with the relevant details of charges for execution of porting withdrawal request of its subscriber to the concerned Donor Operator on a monthly basis and shall deliver such bills to the concerned Donor Operator for each month before the tenth day of the following month or at such periodic intervals and within such time limits as may be mutually agreed upon.
- (5d) The Mobile Number Portability Service provider shall send bills along with the relevant details of the charges for facilitating return of the mobile number after disconnection due to any reason including non-payment, to the number range holder for each month before the tenth day of the following month or at such periodic intervals and within such time limits as may be mutually agreed upon.
- (d) in sub-regulation (6), after the words, “Per Port Transaction charges” and before the words, “within the time limit”, the words, “and subscriber reconnection charges” shall be inserted;
14. Regulation 17A of the principal regulations shall be substituted by the following regulations namely:-
- “17A. Consequence for contravention of the provisions of regulation 6A, or regulation 8, or regulation 9 or regulation 10 or regulation 11 or regulation 12. ---** (1) If any Access Provider or Mobile number Portability Service provider contravenes the provisions of sub-regulation (5) of regulation 8, or sub-regulation (9) of regulation 9 or sub-regulation (2) of regulation 10 or sub-regulation (4) of regulation 11 or sub-regulation (6) of regulation 11, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its licence or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made, or, directions issued, thereunder, be liable to pay an amount, by way of financial disincentive, not exceeding five thousand rupees for each contravention, as the Authority may, by order direct.
- (2) If any Access Provider or Mobile number Portability Service provider contravenes the provisions of regulation 6A or sub-regulation (1) of regulation 10 or regulation 12, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its license or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made, or, direction issued, thereunder, be liable to pay an amount, by way of financial disincentive not exceeding ten thousand rupees for each wrongful rejection of the request for porting, as the Authority may, by order direct.
- (3) No order for payment of an amount by way of financial disincentive under sub-regulation (1) and sub-regulation (2) shall be made by the Authority unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the contravention of the regulation observed by the Authority.

S. K. GUPTA, Secy.

Note 1: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, part III, section 4 vide notification No. 116-4/2009-MN (Vol.II) dated 23rd Sept. 2009 and amended vide:

- (i) Notification no. 116-1/2010 dated 28th January, 2010 (1 of 2010)
- (ii) Notification no. 116-1/2010 dated 24th November, 2010 (5 of 2010)
- (iii) Notification no. 116-5/2012 dated 8th June, 2012 (16 of 2012)
- (iv) Notification no. 116-5/2012 dated 19th September, 2012 (19 of 2012)
- (v) Notification no. 116-4/2013 dated 22nd July, 2013 (9 of 2013)
- (vi) Notification no. 116-19/2014 dated 25th February, 2015 (03 of 2015)

Note 2: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of these regulations.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) dated 23rd September, 2009 laying down the basic business process framework for implementation of intra-circle Mobile Number Portability (MNP) in the country. Facility of MNP was launched in Haryana service area on 25th November 2010 on pilot basis and the same was extended to the entire country on 20th January 2011. Initially, the MNP facility was available within the licensed service area only. However, in accordance with the

provisions contained in the National Telecom Policy- 2012 regarding “One Nation – Full Mobile Number Portability”, full MNP was implemented w.e.f. 3rd July 2015.

2. The reports submitted by Mobile Number Portability Service Providers (MNPSPs) are monitored periodically to study the pattern of rejection of porting requests by the Donor Operator (DO). Analysis of the reports for the period - April, 2016 to March, 2017 indicates that average rejection of porting requests by Telecom Service Providers (TSPs) in all the categories was about 11.16% (total rejections average per month is about 5.87 lakh) and rejections on the grounds of “UPC Mismatch” and “UPC expired” constituted about 40% of the total rejections. With average porting requests per month of 52.35 lakh, the average rejections on the ground of “UPC Mismatch” and “UPC expired” jointly comes out to be approximately 2.3 lakh per month for the period mentioned above. Accordingly, to address the issues faced by the telecom mobile subscribers, draft Telecommunications Mobile Number Portability (seventh amendment), Regulations 2017, was issued on 16th August, 2017 for seeking comments of the stakeholders. The stakeholders were requested to submit their comments till 28th September 2017. In this draft regulation, it was envisaged that Donor Operator upon generation of UPC, shall forward the content and validity of UPC to MNPS, which in turn can be approached by the Recipient Operator, to confirm the correctness and validity of the UPC submitted by the subscriber.
3. The comments received from the stakeholders were examined and analysed. Through the comments it was observed that in addition to the amendments proposed in the draft MNP regulations as mentioned in para above, various other issues were also raised by the stakeholders and new mechanisms were suggested. The suggestions/ comments submitted by the stakeholders during consultation on draft 7th amendment had necessitated further consultation among all the stakeholders.
4. In view of the foregoing, the Authority initiated the consultation process with a vision to review and revamp the existing MNP process and make it more efficient and convenient for the telecom subscribers. Accordingly, a Consultation Paper was issued for the comments of the stakeholders on 6th April, 2018, seeking comments by 3rd May, 2018 and counter-comments by 17th May, 2018, on the issues identified and proposed modifications in the MNP process. In response to the consultation paper, thirteen (13) comments and five (05) counter-comments were received. An Open House Discussion was held at TRAI headquarters on 11th June, 2018.
5. The written comments, counter- comments and views of the stakeholders, presented during the Open House Discussion were examined and after due deliberations, draft Seventh Amendment to the Telecommunication Mobile Number Portability regulations, 2009 (8 of 2009) was prepared and placed on TRAI’s website on 25th September 2018 for comments of the stakeholders. Initially, the draft amendment was formulated on the premise that all the Law Enforcement Agencies (LEAs) will come on board to Central Monitoring System (CMS) before the implementation of the amendment of regulations and accordingly time period of one day was proposed for porting. However, Department of Telecommunications (DoT) meanwhile has communicated to the Authority that on-boarding of LEAs to CMS may take further time. DoT through its communication suggested that timelines for Intra-Licensed Service Area (Intra-LSA) and Inter-Licensed Service Area (Inter-LSA) may be considered for two days and four days respectively. To discuss the way to implement the same, a meeting was held with TSPs and MNPSs in TRAI on 16th August, 2018.
6. The comments on the Draft Seventh amendment were received from nine stakeholders which were thoroughly analysed. Based on detailed analysis and due deliberations, the seventh Amendment Regulations, 2018 to the Telecommunication Mobile Number Portability regulations, 2009 (8 of 2009) are being issued.
7. The explanation of the key issues and the amendments made in the principal regulations are given in the following paragraphs:-

Obligation to set up mechanism for allocation and delivery of unique porting code

8. In the draft amendment, it was envisaged that MNPS be assigned the task of generating and communicating the unique porting code (UPC) to the subscriber intending to port his mobile number. Accordingly, in regulation 6A of the amendment regulations, a process has been outlined for the tasks to be performed by Mobile Number Portability service provider before allocating a UPC. In the revised process, the request for UPC will be received by the access provider and the same will be instantly forwarded to the concerned MNPS. The MNPS, after conducting the requisite checks on a real time basis with the database of the Donor operator, as prescribed, will then generate the UPC and send it to the subscriber.
9. In response to this, some of the stakeholders have reiterated their support for the provisions made in the draft amendment. These stakeholders are of the view that proposed changes in allocation and delivery of UPC will help in providing faster portability and will address the issues of porting rejections. The stakeholders have also opined that

MNPSP being a neutral and third party can ensure an impartial and timely delivery of UPC. One of the stakeholders, seeking no change in the existing process has stated that TSPs are complying with the provisions of the MNP regulations pertaining to the generation of the UPC. Generation of the UPC should remain with the operators and any aberration occurred on the non-generation should be dealt with on case to case basis. The stakeholder also stated that there is a possibility of technical glitches in the system of MNPSP.

10. In the draft amendment, it was indicated that the figures of the rejection of porting requests under the grounds 'UPC Mismatch' and 'Expired UPC' jointly constitute an average of around 45% of the total rejection of porting requests for the period April, 2017 to May, 2018. Also average rejections under the categories 'Payment dues' and 'Less than 90 days' were at 34.50% and 12.89% respectively.
11. In the draft amendment the Authority has already emphasized the facts stated above and have seen no improvement in the rejections in major categories of rejections in the subsequent months, June to September 2018. In the existing process, the subscriber receives the information that his porting request has been rejected only after lapse of four to seven days of submitting his porting request.
12. The Authority has examined the comments and observations submitted by the stakeholders. The Authority is convinced of authorizing the MNPSPs to have preliminary checks of the porting conditions by way of query with the DO before generating UPC. Accordingly, the request for generating the UPC by the subscriber received at DO's network, on Short Code 1900 will be forwarded to the concerned MNPSP which upon examination of the conditions laid down in Regulation 6A of the amendment regulations shall allocate and deliver UPC to the mobile subscriber.

Implementation of revised mechanism for generation and delivery of UPC by MNPSP

13. On the issue of challenges in implementation of revised mechanism for generation and delivery of UPC by MNPSP, some stakeholders have expressed their concerns that it would require upgradation of the present software at MNPSPs' end to accommodate the changes. Further, handling voluminous transactions on real time basis shall be difficult for MNPSPs with the existing infrastructure and shall result in incremental costs. Some stakeholders have submitted that the process envisages sharing of customer information available in the database of RO as well as DO with MNPSPs which has grave implications, not only for the security of database of the TSPs, but shall be in violation of the confidentiality terms under which the information has been collected from the customers. This could also result in misuse of the information by MNPSPs for their commercial gain.
14. Another stakeholder has stated that the existing licence conditions for the MNPSP do not cover the role of MNPSPs as envisaged in the proposed process. Some stakeholders have submitted that in order to reinforce the accountability of MNPSPs, the role and responsibilities of MNPSPs should be clearly defined in the MNP regulations and licensing terms.
15. One of the stakeholders has opined that as MNPSP licence are coming up for renewal in March 2019 and hence DoT, TRAI and MNPSPs should negotiate these terms and mutually agree on a schedule of expanded responsibilities for the MNPSPs and agree to fair and adequate compensation for fulfilling the expanded role.
16. The Authority has examined the comments of the stakeholders and is of the view that there shall not be grave challenges in implementation of the revised process; and it can be implemented with optimum hardware and/ or software changes on the part of TSPs and MNPSPs. It is worth to mention that the systems of TSPs and MNPSPs already have connectivity through the existing gateway links to facilitate the entire MNP process. In order to minimize the impact of the revised process of UPC delivery on the subscribers, operators and MNPSPs, the existing gateways between the service providers and the MNPSPs can be utilized for routing the request of UPC received by Donor operator from the subscriber through SMS, as in the existing process. UPC request message received by the Donor Operator from its subscriber shall be immediately forwarded to the concerned MNPSP for further action. The existing infrastructure / gateways can be gainfully utilized to implement the revised process.
17. On the part of challenges arising out of the licensing terms and conditions, the Authority shall separately deal the matter with DoT to incorporate the role of MNPSPs in the revised scenario by appropriate amendment to the licensing terms of MNPSPs, if deemed required.

Revised process for validation of conditions and generation / delivery of UPC

18. Through the draft amendment, it has been envisaged to establish a query response mechanism to enable the Mobile Number Portability Service Provider (MNPSP) to access the database of the Donor Operator on real time basis to query the conditions listed in Clauses (a) to (h) under sub-regulation (3) of regulation 6A.
19. With regard to the queries listed under sub-regulation (3) of regulation 6A, one of the stakeholders has suggested that it would like to share response to such query in the form of a “Yes” or “No” reply and no other data would be exchanged in the process. The stakeholder also submitted that there is no need to ascertain if the customer is a “Pre-Paid” or a “Post-Paid” as it has no relevance in the porting process.
20. The stakeholder also mentioned to reinforce the accountability of MNPSP for smooth functioning of the porting process, prevention of fraudulent porting, resolution of customer complaints, etc. The stakeholder has proposed some of the actions viz. availability of real-time report and information to all operators, providing information to customers about the completion of stages of porting requests, specifying the status of the request (whether it has been accepted or rejected), address MNP related complaints from the subscribers and agreeable SLA between the RO/DO and MNPSP. The stakeholder has suggested levying appropriate penalty, in case there are any lapses on part of the MNPSP.
21. One stakeholder requested to issue the API specifications alongwith the final regulations, to enable him to start the work. Another stakeholder submitted that it is assumed that query for the subscriber information into the donor database will be done using SOAP messages on the same URL that exists for each of the access provider today. This will help in achieving the desired information from the donor operator with minimal configuration / hardware changes at both MNPSP and access provider’s end.
22. One stakeholder opposing the query response mechanism has stated that this has grave implications for not only the security of the database of the TSPs but will also be the violation of the confidentiality terms under which the information has been collected from the customer. Stakeholder also stated that giving access of complete customer information to MNPSP would be a potential risk of misuse of information by MNPSP for its commercial gain. Therefore, suggested that the respective checks of rejection reasons/acceptance of the MNP request should remain with the operators and any aberration occurring w.r.t. non-compliance of the regulations should be dealt with on a case to case basis.
23. The submission of one stakeholder regarding the confidentiality of the customer information and its potential misuse by MNPSP for commercial gain has been examined. In this regard, it may be noted that MNPSPs are issued license by the Licensor under the Section 4 of Telegraph Act 1885. There are adequate provisions under the license issued to these entities in adhering to the confidentiality clauses.
24. The suggestion of the stakeholder to share response to query in the form of a “Yes” or “No” is agreeable and no other information such as commercially sensitive information will be required to be shared with the MNPSP.
25. The purpose of seeking status of the connection i.e. prepaid or postpaid was to eliminate the query to be made for outstanding dues in case of pre-paid connection. The Authority deliberated upon the suggestions of the stakeholders and is of the view that query related to Prepaid or Post paid status can be eliminated and instead query can be made by MNPSP for “Outstanding dues” in all the cases i.e. pre-paid and postpaid. The response shall be “No” in case of all pre-paid connections and those post paid connections which have no outstanding dues before the date of request for UPC. The response shall be “Yes” only for those postpaid connections, where there is outstanding payment due from the subscriber by way of pending bill or bills, as the case may be, issued as per the normal billing cycle but before the date of request for UPC. According to the foregoing, MNPSP has to perform the queries for the conditions (a) to (g) as defined in sub-regulation (3) of regulation 6A.

Mechanism for monitoring the role of MNPSPs and TSPs in the revised scenario

26. On the issue of accountability and role of MNPSPs in the revised process, some of the stakeholders have stated that there should be a provision for detailed Service Level Agreement (SLA) for each task that MNPSPs shall be required to perform. Some stakeholders have sought for regular reporting mechanism for monitoring while another stakeholder has suggested that periodical inspection, monitoring and auditing by TRAI should be conducted.
27. The accountability of MNPSPs and TSPs in the changed scenario is an important aspect. The accountability can be ensured on measurable parameters for the tasks assigned. Accordingly, the Authority is of the view that apart from the existing reporting requirements, the Mobile Number Portability Service Providers shall generate specific sets of statistics/ reports regarding the number of requests received for UPC from the mobile subscribers, the number of UPC allocated successfully or any other report as required from time to time.

28. In order to monitor the efficacy and role of MNPSP in allocation and delivery of UPC, some stakeholders have opined that suitable Quality of Service parameters, applicable to the activities to be performed by the MNPSPs in the revised process, may be prescribed. To reinforce the accountability of MNPSPs and TSPs for allocation and delivery of UPCs and smooth functioning of the porting process, norms can be specified, keeping in view certain parameters such as number of UPC requests received vis-a-vis number of UPCs generated and number of instances of technical failures or inability to provide the response to the query made by MNPSPs.
29. The Authority has found merits in the suggestions of the stakeholders to include the process of UPC allocation and delivery as Quality of Service (QoS) parameters. The Authority is also aware that role of Donor Operator is crucial in dissemination of the response to the query made by MNPSP. Additionally, in the revised scenario, the roles of MNPSP and RO have been broadened, and hence they shall also be made part of the measurable QoS parameters. These QoS parameters, as deemed fit, shall be notified by the Authority separately.

Validity of Unique porting code

30. In the draft amendment, the validity of the UPC has been proposed for four days for all the licensed service areas except for the licensed service areas of Jammu & Kashmir, Assam and North East where it shall remain unchanged till further decision.
31. Some stakeholders have submitted that the validity of the UPC, has been reduced to 4 Days from 15 Days. These stakeholders have proposed that the UPC expiry should be extended to 7 days instead of 4 days as there is change envisaged in the current subscriber verification & acquisition process.
32. The decision to reduce the validity of UPC to 4 days from the existing provision of 15 days has been taken as since the certain attributes e.g. payment dues, legal aspects etc. of the database accessible to MNPSPs are of dynamic nature and may change within few days. On the aspects of subscriber verification and acquisition process, TSPs are in the testing phase of alternative digital KYC process for new connections. Once the testing and pilots are completed by TSPs, it is anticipated that alternative digital KYC process will be rolled out and also be efficient enough to cater the requirements. Therefore shorter life of UPC is justified. Moreover, UPC can be generated again by the subscriber once it expires; accordingly, the Authority is of the view that validity of the UPC shall be 4 days instead of existing provision of 15 days.
33. The draft regulation has reduced the validity of the UPC to four days for all the license service areas. The exceptions have been mentioned for the licensed service areas of Jammu & Kashmir, North East service areas where the existing provisions shall prevail till further decision. The licensed service area of Assam shall also be treated as included since it has been missed inadvertently in the list of licensed service areas with exceptions. This issue has been pointed by a stakeholder in its comments and has requested for clarity on the issue. Therefore, barring the existing provisions for licensed service areas of Jammu & Kashmir, North Earth and Assam, the validity of UPC shall be 4 days for all the other licensed service areas. In the revised process, the UPC shall be validated by the MNPSP at the time when the request is received from the RO and therefore validity of 4 days shall be sufficient.

Timelines for porting

34. Draft amendment regulation has provisioned for timeline of 2 working days for the porting requests of Intra-Licensed Service Area (Intra-LSA) nature except the requests made under corporate category. The timelines of 4 working days has been provisioned for all the porting requests of Inter-License Service Area (Inter-LSA) and corporate category numbers. The provision mentioned above has been made on the suggestion received from Department of Communications (DoT) to delink the review of MNP timeline process from implementation of Central Monitoring System (CMS), as it may take some time for on-boarding all LEAs on CMS platform. DoT has also suggested TRAI to review the existing provisions and reduce the timelines of 4 working days to 2 working days for clearance by Donor Operators only in case of Intra-LSA MNP requests. Whereas, in case of Inter-LSA MNP requests, the present timelines of 4 working days for clearance by Donor Operators should be strictly adhered to.
35. The benefits of separate timelines for Intra-LSA and inter-LSA have been well explained in the draft regulation and reiterated again. To explore the possible implementation of separate timelines for Intra and Inter-LSA porting request, the data collected from the MNPSPs for the period April, 2017 to June, 2018 indicated that Intra-LSA porting requests are approximately 93 % of the total MNP requests. In order to seek views of TSPs and MNPSPs on the implementation of timelines for Intra-LSA porting requests to two days, a meeting was held in TRAI on 16th August, 2018.
36. On the issue mentioned above, some stakeholders are in agreement with the changes proposed in reduction of time for porting. One of the stakeholders has however, mentioned that the proposed timelines of 2 days and 4 days for intra and inter LSA MNP respectively are still sub-optimum and need to be evaluated for further reduction in the

timeline of the porting process on a continued basis till the targeted objective of near real time number porting has been achieved.

37. Some stakeholders are of the view that the proposed reduction in the MNP process would have been possible if the mandate to remove E-KYC process for subscriber acquisition was not received from DOT. If the earlier customer acquisition process through paper CAF is imposed on the TSPs then it will not only increase the time taken in service activation but will require number of activities on part of recipient operator which will take more than 4 days and in the meantime UPC would have expired. These stakeholders have also proposed that the Inter-LSA porting (in case of intra-operator porting), the timelines can be reduced to two days, as the porting is within an operator and in such cases, the donor and recipient operator is practically the same.
38. In the revised MNP process², the total time for porting shall be reduced for all the subscribers, except for the corporate mobile numbers and inter-LSA porting. The UPC shall be generated by MNPSPs for the mobile numbers, upon querying the database of DO, therefore, it is not required to seek clearance from DO again at the stage of porting of mobile number for non corporate numbers. The issue of additional timelines needed as requested by some stakeholders, to complete the verification and paperwork etc. is not relevant here as the request of porting is submitted post completion of all KYC related activities. MNPSPs shall forward to the DO, only the porting requests of corporate mobile numbers for checking the authorization letter.
39. The Authority has already mentioned in the draft regulation that timelines shall be reviewed once all the Lawful Enforcement Agencies (LEAs) are on-board to CMS. On the proposal to reduce timelines in case of intra-operator (inter-LSA) porting, the Authority is of the view that there shall be practical difficulties in issuing the approval required from the designated Nodal Officer of the States, due to change of LEAs, in two working days, and hence cannot be considered. Accordingly, porting timeline of 2 working days has been provisioned for the porting requests of intra-LSA nature only. The timelines of 4 working days continue to be provisioned for porting of inter-LSA and corporate category numbers.

Withdrawal of Porting Request

40. In the draft amendment, provision has been made for withdrawal of porting request by the customer through SMS within 24 hours of submission of porting request. On this issue some of the stakeholders have opined that as the customer generally approaches his/her current operator (DO) for queries or continuity of his services, therefore he should be informed by MNPSP, of the timing (with date and time) of receipt of the porting request from RO so that customer can avail the facility of withdrawal of porting request, if he so desires. The stakeholders also suggested that MNPSP should inform the subscriber as well as the DO through SMS before processing of his/her porting request in case the subscriber raises the request for withdrawal after the defined timeline of 24 hours.
41. Some of the stakeholders also suggested that in order to prevent misuse of the UPC, post the withdrawal request made by the customer, the UPC generated by the customer shall also become invalid so that no further porting requests are made with the same UPC. Some stakeholders have proposed that the port withdrawal window should be extended to 48 hours instead of 24 hours. Ideally, withdrawal window should be extended to till "port declaration date" by MNPSP so that there is no time limitation for customer to send the cancellation request.
42. The Authority has examined the comments of the stakeholders. On the issue of providing information to the subscriber and DO, the provision has been made that upon receipt of porting request from RO, MNPSP shall send an SMS to the subscriber informing him about the scheduled date and time of porting. In the same message, the subscriber is to be given time window of 24 hours for withdrawal of porting request. In case withdrawal request is executed, UPC shall become invalid. In case, withdrawal request is received after the designated time window of 24 hours for withdrawal, MNPSP shall inform the subscriber through SMS that port withdrawal window has expired and shall proceed with the scheduled date and time of de-activation and activation as per the process defined. MNPSP shall also inform the same to respective DO and RO through internal channel of communication.

Porting of Corporate Mobile Numbers

43. Some stakeholders have suggested that in case of corporate connections bringing the outstanding payment check before the generation of UPC by MNPSP, will lead to an increase in outstanding payment exposure from present 4 working days of porting window to additional 4 days (till UPC validity period). The Corporate connections whose bill generation date falls in between the UPC generation and the actual porting date may lead to an additional

² It is anticipated that the Central Monitoring System installed by Department of Telecommunications would be fully operational in the near future and all the concerned security agencies would use the centralized system. However, as suggested by DoT, timelines for Intra and Inter-LSA porting are to be kept separate till full implementation of CMS.

exposure. The stakeholder also expressed that outstanding payment exposure in case of COCP numbers is much higher than that of an individual subscriber. Thus, the outstanding payment check should be done additionally on receipt of porting request by the Donor Operator.

44. The stakeholder also suggested that MNPSP should reject the porting request wherein the UPC is generated with prefix 'C' but authorization letter not annexed by the recipient operator (RO) and also in cases where the UPC is not prefixed with 'C' but the authorization letter has been shared by the RO.
45. Another stakeholder has requested to permit corporate porting under a single UPC. Stakeholder also proposed that the restriction of only 50 numbers under one authorization letter should at least be removed, if not agreed to permit the corporate porting under single UPC.
46. Regarding the request of the stakeholder on performing the outstanding payment check additionally on receipt of porting request by the Donor Operator, the Authority is of the view that this will add complications to the porting process. The provision of recovery of dues and subsequently on non realisation of dues by the ported subscriber, raising Non Payment Disconnection (NPD) request to the concerned RO are already there in the regulations.
47. The Authority has agreed that corporate porting requests received without authorization letter or vice versa shall not be processed further by the MNPSP.
48. Permitting the porting of all corporate numbers in a single UPC, as suggested by one stakeholder has in-built complications. The issue has been examined thoroughly during the consultation and formulation of Fifth Amendment regulations issued in 2013. Regarding present limit of 50 mobile numbers in a single authorization letter for corporate porting, the Authority has agreed to enhance this limit to 100 mobile numbers per authorization letter.

Payment of pending dues in case of Post Paid subscribers

49. Some stakeholders have suggested that subscribers can be informed to pay billed and unbilled charges by the way of generation of hot bill immediately after generation of UPC or on port validation date, so that the dues are cleared by the subscriber before porting out. The stakeholders have proposed that in the changed business scenario and technological advancement allowing hot/instant billing, the Donor Operator should be allowed to collect all unpaid dues from the customer before the porting itself and the process of Non-payment disconnection can be completely done away with.
50. The Authority analysed the merits and demerits of the proposal stated above and is of the view that allowing generation of hot bill or instant bill for the unbilled usage before porting will add more problems to the subscriber, rather than convenience. As per the existing provisions, the recovery of such unbilled dues at the time of porting can be made by DO even after porting of mobile number. As a consequence of non-payment of dues, the subscriber is liable to lose his mobile number through NPD process.
51. In view of the above, for early realization of pending dues from ported subscribers, the Authority has alternatively allowed DO to raise outstanding bill immediately after the number is ported out from his network. Therefore, after porting of the mobile number, without waiting for the normal billing cycle date, upon raising the bill for unbilled amount, the DO shall have enough time to remind and timely realize the dues from the subscriber.

Contravention of the provisions of MNP Regulations

52. In order to discourage the wrongful rejections of the porting requests and adherence to the timelines specified for the various tasks, the provisions of financial disincentives have been introduced through the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, (Fourth Amendment Regulations, 2012). The Authority is of the view that due to the enhanced role of MNPSPs in the amendment regulations and change in the framework for generating UPC, the accountability of DO and MNPSP shall have to be ensured. In the revised process, it is important that wrongful rejections and providing false/ wrongful information by the DO upon query made by the MNPSP for the process defined under the regulation 6A are to be discouraged. Therefore, in order to protect the interest of mobile subscribers, such contraventions of regulations shall be subject to scrutiny and the imposition of the financial disincentives, if applicable.
53. Upon analysis of the sample of the rejections by Donor Operator as per the existing provisions under regulation 12, it has been noted that there are large number of cases rejected on invalid grounds. Such rejections pose inconvenience to the telecom subscribers to a great extent. Keeping in view the previous experience, the Authority is of the view that in case any Access Provider (acting as Donor Operator) contravenes the provisions of regulation 6A and regulation 12, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its licence or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made, or, direction issued, thereunder, be liable to pay an amount, by way of financial

- disincentive not exceeding ten thousand rupees for each case of providing wrong /false information or each wrongful rejection of the request for porting or for, as the Authority may, by order direct.
54. On the issue of proposed financial disincentives, one of the stakeholders has suggested that Authority may devise a process to bifurcate between a wilful contravention and a technical error due to system failure etc, thus ensuring that the Donor operator is not penalised for an error as a result of system failure.
 55. One stakeholder has mentioned that the Authority proposes to impose fines applicable to the MNPSPs which appear unduly harsh and punitive. The stakeholder while requesting the reasonability of fines has also proposed that a percentage-based service level agreement (SLA) be reached so that a fine should be assessed only if more than a certain percentage of UPCs requests in a reporting period are not generated on time. This can be formed a standard report to the Authority monthly and the fines levied in due course. The fines should be lenient and assessed to become more significant only if there are repeated incidents in consecutive months. Also, care must be taken to define any SLAs to make them specific to the party in question.
 56. The Authority is agreeable to the suggestion that issues/ instances of technical errors can be monitored through QoS mechanism applicable to both i.e. MNPSPs and TSPs. The Authority shall issue appropriate QoS norms to be adhered to separately by MNPSPs and Access Providers. The benchmark or SLA parameters can be put in place to monitor the entire MNP process and Financial Disincentives shall be imposed for the violation or deviation on part of the MNPSPs and Access Providers. The Authority shall consult the stakeholders separately for defining such norms.

Handling of subscriber related issues during allocation and delivery of unique porting code

57. During the allocation and delivery of unique porting code, it is paramount to ensure that UPC is generated for the every request made after checking all the eligibility conditions. A proper and timely communication has also to be made to the subscriber in case his request to port does not qualify to get the UPC or there is any technical issue at that time. This entire process is subject to scrutiny of the Licensor and TRAI. During the process of getting UPC and porting his mobile number, the subscriber may encounter with certain queries / issues with regard to progress of his porting request.
58. Regarding handling of the issues / complaints from the subscribers, one stakeholder sought to reinforce the accountability of MNPSP for smooth functioning of the porting process, prevention of fraudulent porting, resolution of customer complaints, etc. The stakeholder has proposed that MNPSPs shall be responsible to provide the information to customers about the completion of stages of porting requests, specifying the status of the request (whether it has been accepted or rejected), establish Call Centers to address MNP related complaints from the subscribers.
59. Another stakeholder has stated that MNPSPs should not directly interact with subscribers except via SMS because they are not oriented to communicating directly with over a billion end users in multiple languages. Operators have immense resources and call centres and have been doing this efficiently. The stakeholder also submitted that if MNPSPs are to manage end user communication, there will be a need for substantial increase in price provided to them. With a solution to the issue, some stakeholders have proposed that MNPSPs can provide a portal where DO can obtain status of UPC, porting, etc.
60. The Authority analysed the submissions made by the stakeholders and is of the opinion that the subscribers need not interact directly with the MNPSPs mainly for the two reasons. Firstly, the subscribers are familiar with interacting with their service providers, who already have their resources and call centres in place to redress subscribers issues effectively. In contrast, to handle the calls and queries from the subscribers, MNPSPs shall have to replicate similar resources at their end. Secondly, in response to the query made to the database of DO, prior to allocation and generation of UPCs, the MNPSPs shall obtain the information only in the form of 'Yes' or 'No' and hence, MNPSP shall have no other information regarding the various attributes of the subscriber and the specific reasons for rejection of the request. Therefore telecom service providers will be in a better position to address the subscriber queries and complaints and hence mandating MNPSP to handle the calls and queries shall be of no avail.
61. The Authority is however concerned that the subscribers should not be inconvenienced and should be able to get certain information using the technology. Therefore, a web portal and / or App managed by MNPSPs, accessible to the DO as well as to subscriber (OTP based authentication) can be useful in disseminating the information to the subscriber on progress of porting or rejection etc., if any. This will lead to reduction of queries / complaints to TSPs or MNPSPs.

Costs associated with allocation and delivery of unique porting code and sending communications to the subscriber

62. On the subject highlighted above, one stakeholder has stated that as per the Draft Regulation there is no clear party to be responsible for paying the MNPSP for generating the UPCs. MNPSPs expect to see significant incremental costs in generating the UPC. The stakeholder also submitted that currently there is a ratio of near 2 UPC request to 1 port request. Therefore, the MNPSPs should be paid a reasonable tariff for each UPC request processed in addition to processing the request for porting. If the Authority ultimately rules that the tariff for successful ports should include the costs of the UPC generation, then the fee must be adjusted accordingly.
63. On the aspects of the associated costs, the Authority is of the view that Review of Per Port Transaction charges shall be taken up separately and these charges shall include the cost of generating UPCs by MNPSPs and sending SMSs at various stages. Therefore, in this regard a separate consultation shall be taken up with the stakeholders.

Time period for implementation of the amendment

64. In the draft amendment regulations, six months time has been envisaged for implementation after publication in the official gazette. One stakeholder has requested that given the significance of the changes being introduced, the number of entities making the changes, and the need for rigorous testing, the Authority must be prepared for inevitable requests from some parties for an extension.
65. Another stakeholder has stated that that after date of publication of the regulation in Official Gazette, the industry will have 6 months to implement the changes after which the new regulation will come into force. For deployment of new MNP process, MNPSPs and operators may need to procure new hardware and implement large scale software changes in their respective application. It is assumed that a thorough end-to-end process flow testing will also be required with each operator before going live with the new regulation.
66. The Authority is of the view that six months time is adequate to implement the amendment regulations.

Refund of unspent balance in case of pre-paid subscribers

67. In the normal circumstances of porting, the existing regulations do not provide for refund of unspent balance in case of pre-paid subscribers at the time of porting. The Authority has been receiving numerous representations on this issue from subscribers, more so in the cases of recent past, where the services of some of the operators have discontinued at a short notice or all of a sudden. On this issue, many stakeholders made their submissions in response to the Consultation Paper issued by the Authority on 6th April, 2018. Some stakeholders are in favor of making provision for refund of unspent pre-paid balances upon porting. One of the stakeholders had suggested providing refund through Aadhaar linked mobile number and bank account. Whereas, many of the stakeholders have expressed their concerns mainly because the administrative costs in implementing this would be more than the unspent balance in case of most of the pre-paid subscribers.
68. The stakeholders also submitted that the present tariff plans and structure of the existing options with free calls and certain GB data per day have substantially reduced the requirement of keeping prepaid balance in the core account for the subscribers. Stakeholders were also of the view that the talk time balance cannot be converted into equal monetary value that can be refunded to the subscriber at the time of porting, unlike security deposit made by the postpaid subscribers.
69. Based on the comments of the stakeholders during consultation process, the Authority is of the view that in the cases of willful porting by the subscriber in normal circumstances the subscriber has to consume his unspent balance before deciding to port his pre-paid mobile number. In addition to the ordinary porting process certain extraordinary circumstances viz. sudden closure of services, surrender of license / spectrum have been observed in the recent past. In order to safeguard the interest of consumers, the Authority had issued Directions to the concerned service providers to refund unspent balance of pre-paid mobile subscribers. The Authority is of the view that in order to address any unforeseen situations, consequent upon which the subscribers are forced to port out against their own free will, the issues shall be dealt by issuing Directions from time to time as per the prevailing practice.

Reconnection of mobile numbers under Non Payment Disconnection request

70. The consultation paper had raised the issue of restoring the mobile number of subscriber even after Non Payment Disconnection (NPD) request has been raised by the RO to MNPSP, in cases where the subscriber made the payment after disconnection (but before expiry of sixty days ageing). There is no provision for reversing the process in the existing MNP regulation. There have been instances, where subscribers have not been able to make the payments within the notice period due to genuine difficulties, and are willing to pay the entire dues to get back their mobile numbers. But in the existing process, they are unable to get their mobile number back and the number is returned to

the number range holder. Given the fact that in the present scenario, mobile number has gained so much importance that losing it can have serious personal and financial implications, therefore, provision can be made to re-activate subscribers' mobile number in such cases.

71. The stakeholders have agreed that till the time the number has not been returned to the number range holder, the MNPSP can facilitate re-activation of the mobile number once the subscriber has verified with DO and RO, the payment made within the 60 days aging period. On initiation by RO, the MNPSP shall have to terminate the return process. The Authority is of the view that this arrangement shall be beneficial to both DO and RO, as DO is able to recover its outstanding dues from the ported subscriber and RO is retaining the subscriber.

Charges for Ancillary services provided by MNPSP

72. In the consultation paper, issue of ancillary service charges was raised for the comments of the stakeholders. Some stakeholders had suggested that these charges should be paid to the Mobile Number Portability Service Provider for providing the additional services for assigning its resources for Number return, Bulk download of database, Port cancellation and subscriber reconnection activities. Accordingly, the provision of ancillary service charges payable to MNPSP have been made in the regulation for the activities to be performed as mentioned below:
- (a) Provision of 'number return charge' has been made for facilitation of returning the mobile number to Number Range Holder after disconnection due to any reason including non-payment.
 - (b) Provision for 'download charge' has been made for downloading the Number Portability Database by the Access Provider.
 - (c) Provision for 'port cancellation charge' has been made for execution of 'Port withdrawal' request of the subscriber of Donor operator.
 - (d) Provision for 'subscriber reconnection charge' has been made for facilitation of reconnecting the ported subscriber of Recipient Operator in its network.
 - (e) Provision for 'non-payment disconnection charge' has been made for facilitation of disconnection of the mobile number of the postpaid subscriber who has not cleared the dues of the Donor Operator after porting his number.
73. In response to the provisions mentioned above in the draft regulation, among the stakeholder in support of ancillary charges payable to MNPSP, one stakeholder has submitted that it is agreeable with the inclusion of Ancillary Services Charges. Another stakeholder has suggested that Non Payment Disconnect is also a service provided by the MNPSP and "non-payment disconnect charge" payable by the Donor operator should be included.
74. The stakeholders not in support to levying of ancillary service charges have submitted that the Per port Transaction Charge of Rs. 4 which the MNPSP gets from the RO fully covers all the costs. Since the subscribers are presently not being charged in case of reconnection or port cancellation by the RO and DO respectively, the MNPSP should not be allowed to charge the access providers for these activities.
75. The stakeholders also suggested that reconnection of mobile number is purely between the subscriber and the TSP, for which the re-provisioning needs to be done by the TSP only, and they don't see any role to be played by MNPSP, hence there is no reason for paying reconnection charges to the MNPSP.
76. The Authority has examined the comments of the stakeholders. The Authority has taken a view that the provision for Ancillary service charges shall remain in the regulations subject to consultation at the time of defining the actual amount of charges or otherwise will be subsumed in Per Port Transaction charges.

S. K. GUPTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./415/18]